



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06032020-216536
CG-DL-E-06032020-216536

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 58]	नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 28, 2020/फाल्गुन 9, 1941
No. 58]	NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 28, 2020/PHALGUNA 9, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2020

(द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच)

[मामला सं.: (एस जी) 04/2019]

अंतिम जांच परिणाम

विषय : भारत – मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय कदम) नियमावली 2017 के अंतर्गत मलेशिया से भारत में “परिष्कृत प्रक्षालित गंध रहित पामोलिन एवं परिष्कृत प्रक्षालित गंध रहित पाम ऑयल” के आयातों के संबंध में द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच का अंतिम जांच परिणाम।

फा.सं. 22/4/2019-डीजीटीआर.—भारत की जनतांत्रिक सरकार और मलेशिया की सरकार के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सी ई सी ए) के अनुच्छेद 5 और उसके भारत मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय कदम) नियमावली 2017 के संबंध में।

क. प्रक्रिया

भारतीय घरेलू उत्पादकों की ओर से सॉल्वेंट एक्सट्रैक्चर एसोसिएशन (एसईए) ऑफ इण्डिया के द्वारा भारत मलेशिया आर्थिक व्यापक आर्थिक सहयोग करार, (द्विपक्षीय रक्षोपाय कदम) नियमावली, 2017 (इसके पश्चात नियमावली 2017) (जिसे आगे उक्त “नियमावली” अथवा द्विपक्षीय रक्षोपाय नियमावली के रूप में भी कहा जाता है) के अंतर्गत यह

आरोप लगाते हुए एक आवेदन दायर किया गया है कि “परिष्कृत प्रक्षालित गंध रहित पामोलिव 'परिष्कृत प्रक्षालित गंध रहित पाम ऑयल'” (इसके बाद “विचाराधीन उत्पाद” अथवा “पी यू सी” अथवा संबद्ध वस्तुओं के रूप में भी कहा जाता है) का बड़ा हुआ आयात मलेशिया (संबद्ध देश के रूप में भी कहा जाता है) से हुआ है जिसके कारण भारत में समान अथवा प्रत्यक्ष तौर पर प्रतिस्पर्धी उत्पाद के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति हुई है और गंभीर क्षति होने का खतरा है।

2. इसके बारे में संतुष्ट होने पर की द्विपक्षीय रक्षोपाय नियमावली के अनुच्छेद 4 की आवश्यकताओं को पूरा किया गया था, मलेशिया से “परिष्कृत प्रक्षालित गंध रहित पामोलिन, (आर बी डी पामोलीन) और परिष्कृत प्रक्षालित गंध रहित पाम ऑयल” (आर बी डी पाम आयल) के बड़े हुए आयातों की द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच की शुरुआत भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 14 अगस्त, 2019 की जांच शुरुआत की सूचना के द्वारा किया गया था। हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना के तीस दिनों के भीतर अपने विचारों से लिखित रूप में अवगत कराएं।

3. प्रश्नावली मलेशिया में यह उत्पाद निम्नलिखित विदेशी उत्पादकों को भेजा गया था :

- i. फेल्डा मार्केटिंग सर्विसिस सन बीएचडी
- ii. गोल्डन जोमालिना फूड इंडस्ट्री सन बीएचडी
- iii. 101 इडिब्ले ऑयल सन बीएचडी
- iv. केआई-केपोंग इडिब्ले ऑयल सन बीएचडी
- v. मेवहोलियो इंडस्ट्रीज सन बीएचडी
- vi. नगो चैव हाँग ऑयल्स एंड फ्लेट्स (एम) सन
- vii. साउदर्न इडिब्ले ऑयल इंडस्ट्री (एम) सन
- viii. क्वांटस ऑयल सन बीएचडी
- ix. सारवक ऑयल पाम बेहर्ड
- x. सियम डर्बी ऑयल्स लंगत रिफाइनरी
- xi. गोल्डन एग्री रिसोर्सिस लिमि.
- xii. विलमर इंटरनेशनल

4. निम्नलिखित पक्षकारों ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं :

- i. एसओपी एडीबल ऑयल्स एसडीएन. बीएचडी
- ii. साइम दारबी ऑयल्स बिन्दुलू एसडीएन बीएचडी
- iii. बोरनियो एडीबल ऑयल्स एसडीएन. बीएचडी

5. घरेलू उद्योग की प्रश्नावली आवेदक संघ को भेजी गई थी जिसके माध्यम से उन्हें निदेश दिया गया था कि वे निर्धारित प्रपत्र के अनुसार सूचना उपलब्ध कराएं। निम्नलिखित घरेलू उत्पादकों ने क्षति के मामलों से संबंधित सूचना उपलब्ध कराई :

- i. इमामी एग्रोटेक लि.
- ii. लिबर्टी ऑयल मिल्स लि.
- iii. जेमिनि एडीबल फास्ट्स एंड ऑयल्स लि.
- iv. अदनी विलमर लि.
- v. गोकुल एग्रो रिसोर्सेज लि.
- vi. विमल ऑयल एंड फूड्स लि.
- vii. ओजोन प्रोकॉन प्रा. लि.

6. निम्नलिखित आयातकों ने इस जांच में आयातक की प्रश्नावली का उत्तर/अनुरोध प्रस्तुत किए हैं :

- i. बड्जे बड्जे रिफायनरीज लि.
- ii. आरएसएच एग्रो प्रोडक्ट्स लि.
- iii. फिगोरीफिको अल्लाना प्राइवेट लि.

7. घरेलू उद्योग द्वारा अनंतिम रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के लिए किए गए अनुरोध की जांच की गई थी और यह अनंतिम रूप से निर्धारित किया गया था कि नाजुक परिस्थितियां मौजूद थी, जिसके कारण हानि एवं क्षति से घरेलू उद्योग को अंतर्निहित राहत प्रदान करने के उद्देश्य से अनंतिम रक्षोपाय शुल्क लगाना आवश्यक हो गया जिसे ठीक किया जाना मुश्किल हो सकता था। तदनुसार, अनंतिम शुल्क की सिफारिश करते हुए प्रारंभिक जांच परिणाम दिनांक 26 अगस्त, 2019 की अधिसूचना सं. 22/4/2019 के माध्यम से इस नियमावली के नियम 9(2) के अंतर्गत जारी किया गया था। केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 4 सितंबर, 2019 की अधिसूचना सं. 29/2019 के माध्यम से अनंतिम शुल्क लगाया।

8. नियमावली 5 के उप नियम (6) के संबंध में एक मौखिक सुनवाई दिनांक 21 अक्टूबर, 2019 को आयोजित की गई थी। हितबद्ध पक्षकारों अर्थात् घरेलू उद्योग और मलेशिया की सरकार ने इस सुनवाई में भाग लिया और मौखिक अनुरोध किए। महानिदेशक के पद में परिवर्तन के कारण, एक अन्य मौखिक सुनवाई 2006 की सिविल अपील 949 में आटोमोटिव टायर मैनुफैक्चर एसोसिएशन (एटीएमए) बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में पारित निदेश के अनुसार दिनांक 11 दिसंबर, 2019 को मौजूदा महानिदेशक (डीजी) द्वारा की गई थी।

9. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा मौखिक सुनवाई के बाद पेश किए गए लिखित अनुरोधों की प्रति सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई थी। हितबद्ध पक्षकारों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिखित अनुरोधों के संबंध में प्रत्युत्तरों, यदि कोई हो, को प्रस्तुत करने के लिए अवसर भी दिया गया था।

10. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा व्यक्त किए गए सभी विचारों की जांच की गई थी और उपयुक्त निर्धारण करने में इन पर विचार किया गया है। प्राप्त सूचना को अगोपनीय पाठ सार्वजनिक फाइल में रखा गया है।

ख. जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

आवेदक के विचार

11. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध नीचे दिए गए अनुसार हैं :-

क. इस करार के अंतर्गत रक्षोपाय कदमों के लिए आवेदन सोल्वेंट एक्स्ट्रेर एसो. ऑफ इण्डिया के द्वारा कार्य किया गया है और इस कारण से यह माना जाना चाहिए कि यह आवेदन भारत में “परिष्कृत प्रक्षालित गंध रहित पामोलिव परिष्कृत प्रक्षालित गंध रहित पाम ऑयल” के उत्पादकों की ओर से दायर किया गया है।

ख. जांच के अधीन यह उत्पाद “परिष्कृत प्रक्षालित गंध रहित पामोलिव परिष्कृत प्रक्षालित गंध रहित पाम ऑयल” (क्रमशः आर बी डी पाम ऑयल और आर बी डी पामोलिव के रूप में भी जाना जाता है) है, जो एच एस को 15119010 और 15119020 के अंतर्गत आता है।

ग. विचाराधीन उत्पाद का आमतौर पर अस्वास्थ्यकर वसा जैसे नकली मक्खन, लघुकरण और वनस्पति घी तैयार करने के लिए किया जाता है।

घ. ऐसे अनेक उत्पादक हैं जो इस एसोसिएशन के सदस्य हैं और उनमें से नौ सदस्यों ने इस याचिका का समर्थन किया है।

ड. यह एसोसिएशन अलग अलग उत्पादक के आंकड़ों को जैसे उत्पादन, बिक्री, भंडार, लाभ आदि इस तथ्य को देखते हुए नहीं रखता है कि यह व्यापारिक रूप से संवेदनशील आंकड़े हैं और यह एसोसिएशन इस देश में प्रतिस्पर्धा कानूनों को देखते हुए यह कार्यकलाप करने के लिए बाध्य नहीं है।

च. घरेलू उत्पादन के संबंध में सूचना दो स्रोतों से प्राप्त की गई है :

(क) घरेलू कच्चा पाम ऑयल (सी पी ओ) उत्पादन

(ख) आयात किये गये कच्चा पाम ऑयल से।

छ. याचिकाकर्ता यह मानते हुए कि एक मी. ट. कच्चा मालमाल (सी पी ओ) 0.95 मी. ट. परिष्कृत पाम ऑयल का उत्पादन करता है और एक मी.ट. परिष्कृत पाम आयल 0.80 मी.ट. आर बी डी पामोलिन का उत्पादन करता है। संबद्ध वस्तुओं के कच्चे पाम आयल से परिवर्तन गुणक को लागू कर सकल भारतीय उत्पादन प्राप्त किया है।

ज. पाम ऑयल कमरे के तापक्रम पर सेमी-सॉलिड (20 डिग्री से.) है। तरल भाग को भौतिक रूप से विभाजन के द्वारा पाम ऑयल के ठोस भाग से अलग किया जा सकता है। विभाजन के बाद तरल भाग को “पाम ओलिन” कहा जाता है जिसे आमतौर पर बोतल में बंद किया जाता है और कूकिंग ऑयल के रूप में बेचा जाता है। ठोस वसा के भाग को “पाम स्टेयरिन” कहा जाता है जो विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है।

झ. संबद्ध वस्तुओं पर लागू मानक दर 100 प्रतिशत है। हालांकि, लागू दर अधिमान्य प्रशुल्क करारों (मलेशिया के साथ सी ई सी ए) और (ए आई एफ टी ए) के अंतर्गत अधिमान्य सीमा शुल्क जिसे दिनांक 31.12.2018 की अधिसूचना संख्या 82/2018 और 84/2018 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था, के कारण कम है। सीमा शुल्क की लागू की गई दर ए आई एफ टी ए और सी ई सी ए करार के लिए उपलब्ध कराई गई दरों के स्तर से काफी कम रही है और सी पी ओ एवं संबद्ध वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क के बीच अंतर शतप्रतिशत था। लागू की गई दरों में मार्च 2018 में बहुत अधिक वृद्धि हुई। इसके बाद ही ऐसा हुआ कि सी ई सी ए और आशियान के अंतर्गत लागू सीमा दरें संगत हो गईं।

ट. आवेदक ने मलेशिया और भारत सरकार (सी ई सी ए) के बीच किये गये व्यापक आर्थिक सहयोग करार के अनुसरण में इस आवेदन को दायर किया है।

ठ. सी ई सी ए के अनुसरण में, मलेशिया से कच्चे पाम ऑयल (संबद्ध वस्तुओं का कच्चा माल) के आयातों पर शुल्क को 40 प्रतिशत तक कम किया गया है जबकि संबद्ध वस्तुओं पर शुल्क दिनांक 31.12.2018 के अधिसूचना सं. 82/2018 के माध्यम से 45 प्रतिशत तक कम किया गया है। इस प्रकार से कच्चे माल ऑयल और संबद्ध वस्तुओं पर शुल्क के बीच अंतर केवल 5 प्रतिशत है।

ड. कच्चे पाम ऑयल और संबद्ध वस्तुओं पर शुल्क के बीच अंतर हमेशा 10 प्रतिशत रहा है। कच्चे पाम ऑयल और संबद्ध वस्तुओं के बीच 10 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक शुल्क के अंतर में कमी के बाद संबद्ध वस्तुओं के मलेशिया से आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है।

ढ. जांच की अवधि में आयात की मात्राओं में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। आयातों में 2015-16 से जांच की अवधि तक 516 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। भारत में संबद्ध उत्पाद के आयातों में स्वतंत्र रूप में तथा उत्पादन, खपत और आयातों में हिस्से की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि हुई।

ण. उत्पाद और खपत की तुलना में आयातों में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई है। 2015-16 में भारतीय उत्पादन में हिस्से का 8 प्रतिशत आयात हुआ था जो जांच की अवधि में 73 प्रतिशत तक बढ़ गया। इसी प्रकार से 2015-16 में भारतीय खपत में हिस्से का 5 प्रतिशत आयात हुआ जो बढ़कर जांच की अवधि में 32 प्रतिशत हो गया।

त. मलेशिया से आयात जो 2015-16 में कुल भारतीय आयातों का केवल 17 प्रतिशत था, बढ़कर प्रस्तावित जांच की अवधि में कुल आयातों का 78 प्रतिशत हो गया।

थ. भारत में आयात व्यापक तौर पर इण्डोनेशिया और मलेशिया से हुए हैं। लेकिन मलेशिया के पास भारत – मलेशिया सी ई सी ए के अंतर्गत आर बी डी पामोलिव के लिए शुल्क लाभ है और इस कारण से इस देश में अब मलेशिया से संबद्ध वस्तुओं की भारी मात्रा में आवक हो रही है।

द. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किये जा रहे समान उत्पाद वही है जो आयात किया गया उत्पाद अर्थात् “परिष्कृत प्रक्षालित गंध रहित पामोलिव परिष्कृत प्रक्षालित गंध रहित पाम ऑयल” है। घरेलू उत्पाद की तुलना आयात किये गये उत्पाद से की जा सकती है।

ध. इस उद्योग को उत्पादन की क्षमताओं का पूर्ण रूप से कम उपयोग के कारण हानि हो रही है। घरेलू उत्पादकों की कठिनाइयों को बढ़ाने के लिए, आयातों में अचानक वृद्धि के कारण भारत में घरेलू उत्पादकों की क्षमता के उपयोग पर आगे और प्रभाव पड़ रहा है।

न. आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि चूंकि इस उत्पाद को भंडार में बहुत अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता है फिर भी इन्होंने बिक्री के रूप में उत्पादन पर विचार किया है।

प. आयातों में मलेशिया का हिस्सा अप्रैल-दिसंबर, 2018 के दौरान 12 प्रतिशत था और अन्य देशों का हिस्सा 88 प्रतिशत था। हालांकि दिसंबर के बाद मलेशिया के आयातों के हिस्से में 78 प्रतिशत तक उछाल आया जबकि अन्य देशों के बाजार हिस्से में 22 प्रतिशत तक गिरावट आई।

फ. तिमाही विश्लेषण यह दर्शाता है कि उत्पादन की तुलना में आयातों के हिस्से में 2018 की तीसरी तिमाही में 2 प्रतिशत तक गिरावट आई थी जो 2019-20 की पहली तिमाही में 75 प्रतिशत तक बढ़ गई थी। इसी प्रकार से, खपत की तुलना में आयातों के हिस्से में 2018-19 की तीसरी तिमाही में 1 प्रतिशत तक गिरावट आई थी जो 2019-20 की पहली तिमाही में 40 प्रतिशत तक बढ़ गई थी। इस प्रकार, स्वतंत्र और सापेक्ष रूप में आयातों में जांच की अवधि में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि हुई है।

ब. आयातों में संपूर्ण उछाल जनवरी, 2019 में सीमाशुल्क में परिवर्तन के बाद हुआ है। इस कारण से, घरेलू उद्योग को क्षति की जांच तत्काल पूर्व वर्ष (अर्थात् उछाल से पूर्व की अवधि) की तुलना में जनवरी-जून, 2019 की अवधि पर विचार करते हुए की जानी अपेक्षित है।

भ. उत्पादों/बिक्री में गिरावट जांच की अवधि (जनवरी-जून, 2019) के उत्पादन और बिक्री के साथ अप्रैल-दिसंबर, 2018 की अवधि से तुलना किए जाने पर स्पष्ट हो जाती है। अप्रैल-दिसंबर, 2018 में भारतीय उत्पादन/बिक्री *** मी.ट. थी जो जांच की अवधि में गिरकर *** मी.ट. हो गई है। अर्थात् इसमें 2.4 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आई। घरेलू उद्योग इस बाजार में आयातों के मौजूद रहने के कारण संबद्ध वस्तुओं की बिक्री करने में सक्षम नहीं हो पाया है, जिसने घरेलू बाजार पर कब्जा कर लिया है।

म. घरेलू बाजार की क्षमता के उपयोग में आयातों में उछाल के साथ उल्लेखनीय रूप में कमी आयी है। जबकि क्षमता का उपयोग उछाल शुरू होने के पूर्व 43 प्रतिशत था, इसमें उछाल के ठीक दो तिमाहियों में 39 प्रतिशत तक और इसके बाद 31 प्रतिशत तक गिरावट आई।

य. घरेलू उत्पादकों के पास अत्यधिक मात्रा में कम उपयोग की गई क्षमताएं हैं। यह उद्योग मलेशिया से आयातों में वृद्धि के कारण मांग में वृद्धि के बावजूद अपनी क्षमता का उपयोग करने में सक्षम नहीं रहा है।

र. घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से में उछाल के पूर्व की अवधि में 69 प्रतिशत तक बिक्री हुई थी, उसमें आयातों में उछाल की ठीक दो तिमाहियों में 65 प्रतिशत और उसके पश्चात 54 प्रतिशत तक गिरावट आई।

ल. आरबीडी पामोलिन के उत्पादन और बिक्री से घरेलू उत्पादकों के लाभ में आयातों में उछाल के साथ जबरदस्त रूप से गिरावट आई है। घरेलू उत्पादक आयात किए गए कच्चे तेल का प्रसंस्करण करने के बाद आरबीडी पामोलिन की आयात कीमत से मुकाबला नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह इसे अपनी लागत की वसूली कर पाना भी मुश्किल बना देगा। इस प्रकार, अन्य घरेलू उत्पादकों ने बाजार में मौजूद रहने के उद्देश्य से आर बी डी पामोलिन का आयात करना शुरू कर दिया है। इसके फलस्वरूप, घरेलू उत्पादकों ने आर बी डी पामोलिन के उत्पादन और बिक्री से बहुत अधिक लाभ खो दिया है।

व. आयातों के कारण घरेलू कीमतों पर न्यूनकारी प्रभाव पड़ रहा है और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग उत्पादन क्रियाकलाप शुरू करने में सक्षम नहीं है।

र. घरेलू उद्योग को पहले से गंभीर क्षति के अलावा, उत्पाद के बढ़े हुए आयात के कारण इस उद्योग को गंभीर क्षति का खतरा उत्पन्न हो रहा था क्योंकि (क) आयातों की मात्रा में अपेक्षाकृत कम समयावधि में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है (ख) घरेलू और आयातित उत्पाद के बीच कीमत में अंतर के कारण मलेशिया से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में वृद्धि हुई है। (ग) मलेशिया के उत्पादकों के पास बहुत अधिक मात्रा में उपयोग न की गई क्षमताएं हैं जिसके परिणामस्वरूप मलेशिया के उत्पादक और निर्यातक लगातार यथासंभव अतिरिक्त बाजारों की तलाश कर रहे हैं (घ) मलेशिया के उत्पादक इंडोनेशिया के बाद विश्व में संबद्ध वस्तुओं के सबसे बड़े उत्पादकों और निर्यातकों में से एक हैं।

ल. मलेशिया के उत्पादकों को पर्याप्त सरकारी सहायता का मिलना उन्हें शुल्क में अपर्याप्त अंतर की स्थिति में सक्षम बनाए रखना जारी रहेगा। मलेशिया की सरकार संबद्ध वस्तुओं के मूलभूत चरण से उत्पादक/प्रसंस्करणकर्ता को प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी के रूप में पर्याप्त सहायता देता है।

व. मलेशिया की सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न सब्सिडी के फलस्वरूप भारतीय उत्पादकों की तुलना में मलेशिया के उत्पादकों के लिए इस उत्पाद के उत्पादन की लागत अपेक्षा से कम हो जाती है। इसके फलस्वरूप जैसे ही सीमाशुल्क में अंतर पूर्व 10 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हुआ, मलेशिया से आयातों में उछाल आ गया।

श. आवेदक इस अवधि के लिए रक्षोपाय कदम उठाने का अनुरोध करते हैं जिसके लिए 10 प्रतिशत से कम शुल्क में अंतर होगा। जबकि, शुल्क में 10 प्रतिशत अंतर अपने आप में पर्याप्त नहीं है, फिर भी वह घरेलू उद्योग को पहुंचाई जा रही मौजूदा क्षति को रोकने के लिए इस उद्योग के लिए न्यूनतम है।

ष. एम आई सी ई सी ए के अनुच्छेद 5 में "अधिसूचनाओं और परामर्शों" के संबंध में प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 5.6 (1) यह कहता है कि द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच की शुरुआत करने वाले पक्षकार का यह दायित्व है कि वह इस प्रकार की जांच की शुरुआत किए जाने के तत्काल बाद अन्य पक्षकार को सूचित करे जिसे वर्तमान मामले में किया गया है।

ह. अनुच्छेद 5.6 (6) में निश्चयात्मक उपायों का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 5.5 (5) में विशेष रूप से अनंतिम उपायों का उल्लेख है। यह देखा जा सकता है कि इन परामर्शों को वर्तमान मामले में अन्य पक्षकार अर्थात् मलेशिया से अनुरोध के तत्काल बाद शुरू किया जाएगा। इस प्रकार अनंतिम उपायों की अधिसूचना के बाद, जी ओ एम इस प्रकार के परामर्श प्राप्त कर सकता है। हालांकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें भारत सरकार के लिए यह अपेक्षित है कि वह अंतरिम उपाय लागू करने के पूर्व परामर्श करे। इस सीमा तक जी ओ एम के तर्कों का कोई पर्याप्त कानूनी आधार नहीं है।

क्ष. मलेशिया की सरकार द्वारा प्रस्तुत लिखित अनुरोधों के पैरा 6.2 के बारे में पूर्ण रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है। अत्यधिक गोपनीयता के ऐसे दावों में आवेदक को किसी टिप्पणी, चाहे जो भी हो, को उपलब्ध कराने से रोक दिया है। आवेदक इस विशेष तर्क के लिए अन्य प्रस्ताव द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों का प्रत्युत्तर देने में सक्षम नहीं है जिनके संबंध में गोपनीय होने का दावा किया गया है। किसी भी प्रकार से पक्षकारों को समग्र तर्क को गोपनीय के रूप में दावा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और गोपनीय के रूप में किसी सूचना के बारे में दावा करने का उचित आधार होना चाहिए।

त्र. मांग और आपूर्ति में कोई अंतर नहीं है। इस उत्पाद के लिए भारतीय क्षमताएं 1.30 करोड़ मी.ट. के आसपास हैं जो किसी देश में उत्पाद के लिए मांग के बहुत अधिक हैं। भारतीय उद्योग के पास इस देश में इस उत्पाद के लिए मौजूदा और भावी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमताएं हैं।

ज्ञ. प्रारंभिक जांच परिणाम का पैरा 29 यह दर्शाता है कि भारतीय घरेलू उत्पादन 2017-18 में *** था और यह भारतीय खपत का लगभग 66 प्रतिशत था। इस प्रकार, मांग में वृद्धि के साथ भारतीय उत्पादन में 9 प्रतिशत तक अर्थात् *** मी.ट. तक गिरावट के लिए विशेष रूप से तब कोई कारण नहीं है जब भारतीय उद्योग के पास अतिरिक्त क्षमता है।

कक. भारतीय क्षमता इस देश में खपत की सीमा में हमेशा से अधिक रही है। इसे मलेशिया की सरकार द्वारा भी अपने अनुरोध में नोट किया गया है। इस प्रकार, आयातों के लिए एक कारण के रूप में उत्पादन करने हेतु घरेलू उत्पादकों की अक्षमता को बचाना निराधार और अनप्रयुक्त है जब उसे सरकार के स्तर पर किया गया है। कम कीमत पर आयातों में अत्यधिक वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग अपने उत्पादन को कम करने के लिए विवश हो गया है।

खख. घरेलू उत्पादकों द्वारा किए गए आयातों के सच को आवेदक द्वारा आवेदन के चरण में ही विचार कर लिया गया था। ये आयात केवल इस कारण से हो रहे हैं कि आयात किया गया संबद्ध वस्तु आर बी डी पामोलिन में प्रसाधित सी पी ओ की लागत से बहुत कम कीमत पर उपलब्ध है। यह तथ्य कि आयात कम कीमतों पर हो रहे हैं, और घरेलू उद्योग सी पी ओ का आयात नहीं कर सकता है, उसे प्रसाधित नहीं कर सकता है और संबद्ध वस्तुओं को समान कीमतों पर नहीं देख सकता है, उत्पादकों द्वारा स्वयं आर बी डी पामोलिन के आयातों से सिद्ध हो जाता है। कोई भी उत्पादक परिष्करण क्षमताओं में निवेश नहीं करेगा और तत्पश्चात् उसे निष्क्रिय नहीं रखेगा और आयातों का सहारा नहीं लेगा। यह आश्चर्यजनक बात है कि बहुत बड़े पैमाने पर निवेश एवं रोजगार के साथ रिफायनरी अल्क काल के व्यापारियों में परिणत हो रहे हैं।

गग. घरेलू उद्योग को क्षति को इस तथ्य से रेखांकित किया गया है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन में 2016 में *** मी. ट. से 16.22 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2019 में *** मी.ट. तक वृद्धि को दर्शाया है। हालांकि वह मांग में वृद्धि के बावजूद जांच की अवधि में इसके पश्चात् बहुत कम समय में गिरकर *** मी.ट. हो गया है। इसके अलावा, चूंकि शुल्क के अवसरों में 1 जनवरी, 2019 से बदलाव हुआ है, अतः महानिदेशक को ठीक उसके पूर्व की स्थिति पर विचार करना चाहिए और उसकी तुलना उसके बाद की स्थिति से करनी चाहिए।

घघ. भारतीय उद्योग को पहले से ही अतिरिक्त अप्रयुक्त क्षमताओं का सामना करना पड़ रहा था और आयातों में उछाल के साथ, इस उद्योग की क्षमता के उपयोग में बहुत अधिक गिरावट आई है। भारतीय उद्योग अपनी क्षमताओं के

आधे का भी उपयोग नहीं कर रहा है। अनंतिम जांच परिणाम का पैरा 42 अपने आप में यह दर्शाता है कि 2019 – 20 की पहली तिमाही में केवल 31 प्रतिशत तक की गिरावट आई थी जो 2018-19 की तीसरी तिमाही (उछाल के पूर्व की अवधि) में 43 प्रतिशत थी। चूंकि शुल्क के अवसरों में 1 जनवरी, 2019 से बदलाव हुआ है, अतः महानिदेशक को ठीक उसके पूर्व की स्थिति पर विचार करना चाहिए और उसकी तुलना उसके बाद की स्थिति से करनी चाहिए।

डड. यह स्वीकार किया गया है कि इस उद्योग को अन्य कारकों के कारण भी हानि होती रही थी। हालांकि आयातों में अत्यधिक वृद्धि के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की क्षमता में और आगे गिरावट आई है और घरेलू उद्योग की व्यवहार्यता पर प्रभाव पड़ा है। जनवरी, 2019 से जून, 2019 के दौरान दावा की गई क्षति का कारण मलेशिया के आयातों में उछाल है जबकि पूर्व की अवधियों में क्षति का कारण मलेशिया से आयातों में उछाल को छोड़कर अन्य कारण थे। महानिदेशक को उछाल की अवधि के दौरान और शुल्क में अंतर के मुद्दे, जिसके फलस्वरूप उछाल आया, में कारणात्मक संबंध देखना चाहिए।

चच. इंडोनेशिया से आयातों का हिस्सा वर्ष 2016 से 2018 के बीच बहुत अधिक था। हालांकि, जनवरी, 2019 से जून, 2019 की अवधि के दौरान इसमें परिवर्तन हुआ। जी ओ एम ने स्वयं इस समस्या को दर्शाया है। जब इंडोनेशिया के उत्पादक आयातों में अग्रणी थे, क्यों मलेशिया से आयातों में इतनी अधिक वृद्धि हुई। इस प्रश्न का उत्तर सीमाशुल्क के अंतरों में है और उसका समाधान इस अंतर को दूर कर किया जाना अपेक्षित है।

छछ. यह उद्योग उस अवधि के लिए इस करार के अंतर्गत अनुमत्य उपायों की अधिकतम सीमा तक संरक्षण दिए जाने का अनुरोध करता है जिसके लिए शुल्क में अंतर 10 प्रतिशत से कम होगा।

जज. उत्पादन और क्षमता के उपयोग में गिरावट को कच्चे पाम आयल के आयातों में गिरावट से भी देखा जा सकता है। सीपीओ के आयातों में इस अवधि के दौरान तेजी से गिरावट आई।

झझ. भारतीय उद्योग अपनी क्षमताओं के एक तिहाई से कम पर अपने संयंत्र को चला रहा है। जबकि इस देश में आर बी डी की खपत 80 लाख मी. ट. तक है, फिर भी इस देश में 130 लाख मी. ट. तक की क्षमताएं हैं। इस प्रकार से आर बी डी पामोलिन का आयात पूर्ण रूप से आवश्यक नहीं है।

टट. विचाराधीन उत्पाद के प्रसंस्करण में लगाये गये मानव घंटों की संख्या वर्तमान अवधि में कम हो गई है। *** लाख तक उत्पादन की वार्षिक हानि पर विचार करते हुए, इस उत्पाद के लिए लगाये गये रोजगार में लगभग *** तक कमी आई है।

ठठ. भारतीय उद्योग की उत्पादकता में जांच की अवधि में बहुत अधिक गिरावट हुई है। ऐसा कोई अन्य कारक नहीं है जिसे बढ़े हुए आयातों को छोड़कर घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति का कारण माना जा सकता है।

डड. आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों की तुलना में पर्याप्त रूप से कम है। घरेलू उद्योग बिक्री अवसरों तथा सामान्य मार्जिन की हानि उठा रहा है। इसके परिणामस्वरूप बिक्री, लाभ, निवेश पर लाभ और नकद प्रवाह कम कीमत के आयातों के लगातार होने के कारण कम हो रहा है।

ढढ. बढ़े हुए आयातों के फलस्वरूप आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में कमी हुई है। आवेदक ने इस नियमावली, के अंतर्गत किये गये प्रावधान के अनुसार रक्षोपाय कदम का अनुरोध किया है। कच्चे ऑयल की आयात कीमत, शामिल प्रसंस्करण लागत और उचित लाभ (5 प्रतिशत) और आयातों की पहुंच कीमत पर विचार करते हुए लक्ष्य कीमत के बीच कीमत में अंतर लगभग 18 प्रतिशत है।

णण. रक्षोपाय कदम की मांग करने का उद्देश्य घरेलू उद्योग को इसकी क्षमता के उपयोग में सुधार लाने में समर्थ बनाने के लिए है, जिससे कि घरेलू उद्योग जिंदा रह सके। आवेदक ने एक वक्त के लिए रक्षोपाय उपायों का अनुरोध किया है। आवेदक ने एक वर्ष अनंतिम रक्षोपाय उपायों को लगाये जाने के लिए भी अनुरोध किया है। यह अनुरोध किया गया था कि अंतरिम उपाय विचाराधीन उत्पाद के बढ़े हुए आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में तेजी से गिरावट को देखते हुए आवश्यक है।

तत. यह भी अनुरोध किया गया था कि मलेशिया से आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है जबकि भारतीय उद्योग से उत्पादन, बिक्री और उसके परिणामस्वरूप क्षमता के उपयोग में पर्याप्त रूप से गिरावट आई है।

थथ. जबकि भारत सरकार कुछ समय के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उठाई जा रही क्षति का समाधान करने के लिए पाटन, सब्सिडी अथवा सामान्य रक्षोपाय कार्रवाई करने पर विचार कर सकती है, जो भी कार्रवाई की जाती है, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच सी पी ओ और आर बी डी पामोलिन के बीच पूर्व के मौजूदा अंतर का समाधान एक स्वतंत्र मसले

के रूप में किए जाने की आवश्यकता है। अन्य कार्रवाई करने से सीमाशुल्क के स्तरों में परिवर्तन किए बिना इस मुद्दे का समाधान नहीं होगा। इस प्रकार से, अन्य कार्रवाई करते समय किसी भी स्थिति में मौजूदा रक्षोपाय शुल्क की पुष्टि किए जाने की आवश्यकता है।

दद. पृथक् रूप से आशियान करार और वर्तमान करार के अंतर्गत मूल सीमाशुल्क में 1 जनवरी, 2020 से बदलाव आया है। जबकि, कच्चे और परिष्कृत ऑयल के बीच अंतर घरेलू उत्पादकों के सतत प्रचालनों के लिए पर्याप्त नहीं है, किसी भी स्थिति में इन दोनों करारों के अंतर्गत सीमाशुल्क अब एक नहीं हो सकता है। इस कारण से आशियान करार के अंतर्गत समान शुल्क के बिना वर्तमान करार में रक्षोपाय शुल्क एक निरर्थक रक्षोपाय शुल्क होगा क्योंकि उपभोक्ता आशियान करार के अंतर्गत लाभ का उपयोग कर पाएंगे।

धध. हालांकि चूंकि संबद्ध वस्तुओं का आयात अब प्रतिबंधित सूची के अंतर्गत है, अतः यह प्रतीत होता है कि इस उत्पाद को अब विनियमित किया जाएगा। हाल के इस घटनाक्रम को देखते हुए, ऐसा लगता है कि 6 महीने की वर्तमान अवधि से आगे रक्षोपाय शुल्क लगाना आवश्यक नहीं हो सकता है। हालांकि इस चरण में किसी अप्रत्याशित घटना के कारण भविष्य में स्थिति में कोई परिवर्तन होगा तब किसी भी स्थिति में उद्योग उपयुक्त निवारण के लिए सरकार से सही तरीके से संपर्क करेगी।

मलेशिया सरकार (जीओएम)के विचार

12. मलेशिया सरकार द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं :-

क. डी जी टी आर, सी ई सी ए में प्रतिबद्धताओं का पालन नहीं कर पाया है क्योंकि मलेशिया की सरकार को अनुच्छेद 5.6 (5) के अनुसार दिनांक 14 अगस्त, 2019 को रक्षोपाय कदम आरंभ किए जाने के पूर्व परामर्श के लिए समुचित अवसर नहीं दिया गया था।

ख. उत्पादन और खपत की तुलना में आयातों पर आरंभिक जांच परिणाम के पैरा- 29 के अनुसार, आवेदक भारतीय बाजार में मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। मलेशिया से आयात 2018-19 में भारतीय खपत का लगभग 9.28 प्रतिशत मात्र था, जबकि भारतीय उत्पादन की तुलना भारतीय खपत से की गई थी और यह 57.52 प्रतिशत था। भारतीय उत्पादन अकेले 2018-19 की अवधि में तथा जांच की अवधि के दौरान भी भारती की खुल खपत को पूरा करने में तब भी सक्षम नहीं था।

ग. उत्पादन और बिक्री की तुलना में आयातों का प्रभाव गिरती हुई प्रवृत्ति को दर्शा रहा है। इस कारण से भारत में घरेलू उद्योग को इन आयातों ने क्षति नहीं पहुंचाई। क्षमता का उपयोग 21 प्रतिशत से 43 प्रतिशत के बीच रहा है। इस प्रकार से यह भारतीय उद्योग की एक समस्या है और यह मलेशिया से किए गए आयातों का परिणाम नहीं है।

घ. एम आई टी आई ने एम आई सी ई सी ए के पैरा 6 के अनुसार परामर्श के लिए अनुरोध किया।

ड. आवेदक भारतीय विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) की स्थानीय मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं रहा है। यह जांच की अवधि (पीओआई) के दौरान स्पष्ट है, भारत में घरेलू उत्पादन भारत की घरेलू उत्पादन का 59 प्रतिशत अथवा *** मी. टन है (प्रारंभिक जांच परिणाम का पैरा 29 का संदर्भ लें)।

च. 2018-19 की अवधि के दौरान मलेशिया से आयात कुल भारतीय उत्पादन का केवल 53.55 प्रतिशत और भारत के कुल उत्पादन का 31.76 प्रतिशत था। इस संबंध में, भारतीय उत्पादन अकेले जांच की अवधि के दौरान तक 2016 की अवधि में भारत की कुल खपत को पूरा करने में सक्षम नहीं था और इसलिए यह विचाराधीन उत्पाद के आयातों के स्रोतों पर निर्भर है (प्रारंभिक जांच परिणाम का पैरा 29 का संदर्भ लें)।

छ. इस जांच में याचिकाकर्ताओं के रूप में नामित कंपनियां मलेशिया से विचाराधीन उत्पाद का आयात करती रही है। यह इस तथ्य को सुनिश्चित करता है कि भारत में घरेलू उद्योग घरेलू मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है और इसके साथ ही यह लागत के मामले में सक्षम नहीं है। इस कारण से उन्होंने या तो आगे प्रोसेस करने अथवा इसका घरेलू स्तर पर व्यापार करने के लिए मलेशिया से विचाराधीन उत्पाद का आयात करने का विकल्प अपनाया है।

ज. घरेलू उद्योग के उत्पादन में 2016 में *** मी.ट. से 2019 में *** मी.ट. तक अर्थात् 16.22 प्रतिशत तक वृद्धि दर्शाया है। घरेलू मांग में भी इसी अवधि के दौरान 4.26 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।

झ. भारतीय घरेलू उद्योग अपनी उत्पादन क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाया। यह पैरा 42 में तालिका में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया था कि भारतीय घरेलू उद्योग की क्षमता का उपयोग वर्ष 2016 से जांच की अवधि के बीच 31 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक ही रहा है।

ट. मलेशिया से आयात घरेलू उद्योग द्वारा उठाई जा रही क्षति का कारण नहीं है क्योंकि अकार्यक्षम क्षमता का उपयोग वर्ष 2016 से देखा गया है। मलेशिया से आयात इस वर्ष में घरेलू उद्योग के उत्पादन का 15 प्रतिशत और जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन का 54 प्रतिशत था।

ठ. घरेलू उद्योग के पास वार्षिक रूप में *** मी.ट. तक उत्पादन करने की विशाल क्षमता है। मांग और आपूर्ति के बीच हमेशा बहुत बड़ा अंतर रहा है जिसके कारण जांच की अवधि के दौरान घरेलू मांग *** मी. ट. थी, लेकिन घरेलू उत्पादकों द्वारा आपूर्ति केवल *** मी.ट. था। मांग और आपूर्ति में अंतर की भरपाई कंपनियों द्वारा आयातों से की गई है, जिन्हें अन्य के साथ-साथ विचाराधीन आयातित उत्पाद के लागत लाभ के कारण इस जांच में याचिकाकर्ताओं के रूप में नाम दिया गया है।

ड. उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री के संबंध में भारतीय घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन 2016 से औसत दर्जे का रहा है।

ढ. इंडोनेशिया से आयातों का हिस्सा भी 2016 से 2018 तक के बीच मलेशिया से आयातों के हिस्से की तुलना में सतत रूप से अधिक रहा है।

ण. यदि रक्षोपाय कदम का उद्देश्य मलेशिया से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के विरुद्ध भारत में घरेलू उत्पादकों/रिफाइनरों का संरक्षण करना है, तब डी जी टी आर से यह आग्रह किया जाता है कि वे एक वैश्विक रक्षोपाय कदम आरोपित कर इंडोनेशिया अथवा अन्य देशों के विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक/निर्यातक जैसे सभी स्रोतों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों को रोके। इस द्विपक्षीय रक्षोपाय कदम को आरोपित कर, अन्य स्रोतों अर्थात् विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने/निर्यात करने वाला देश इंडोनेशिया अथवा अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि देखी जाएगी और इस प्रकार से घरेलू उद्योग को संरक्षण प्रदान करने का उद्देश्य विफल हो जाएगा।

आरएसएच एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड, गुवाहाटी तथा बज बज रिफायनरीज लि. के विचार

13. आरएसएच एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड, गुवाहाटी तथा बज बज रिफायनरीज लि. द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं :-

क. सरकार का आर पी ओ और सी पी ओ के बीच 15 प्रतिशत का शुल्क में अंतर हुआ करता था, लेकिन मलेशिया से हाल में की गई शुल्क में वृद्धि के बाद, शुल्क में यह अंतर घटकर 10 प्रतिशत हो गया है जो रिफाइनरों के लिए सफल रहना मुश्किल बना देता है।

ख. मौजूद अंतर और शुल्क मूल्य बहुत कम है, जो घरेलू खाद्य तेल रिफाइनरों के लिए एक प्रतिकूल स्थिति भी है, यह सुझाव दिया जाता है कि कम से कम 40-50 डॉलर का अंतर बनाए रखा जाना चाहिए।

ग. पड़ोसी देशों जैसे बंगलादेश, नेपाल, श्रीलंका आदि से परिष्कृत पाम आयल का आयात मूल्यवर्धन मानदंडों के अध्याधीन 0 प्रतिशत से कम है। पाम आयल का उत्पादन मुख्य रूप से मलेशिया और इंडोनेशिया में किया जाता है। हालांकि, एस ए एफ टी ए के कारण ये शुल्कों से बचने की कोशिश कर रहे हैं।

घ. घरेलू उद्योग के हित की रक्ष करने के लिए यह अनुरोध किया जाता है कि (क) आर पी ओ और सी पी ओ के बीच सीमाशुल्क में अंतर को कम से कम 15 प्रतिशत पर कायम किया जाए। (ख) आर पी ओ और सी पी ओ के बीच अंतर प्रशुल्क मूल्य को अधिकतम कर 40-50 डॉलर तक किया जाए (एस ए एफ टी ए और सार्क देशों के अंतर्गत खाद्य तेल के आयातों पर प्रतिबंध लगाया जाए) (ग) डी आर आई से अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना एस ए एफ टी ए के अंतर्गत सार्क देशों से खाद्य तेलों के आयातों को प्रतिबंधित करना (घ) पूर्व उत्तर में रिफाइनरियों को सीमाशुल्क राशि का 15 प्रतिशत विशेष छूट/ रिफंड दिया जाए क्योंकि वे भूमि से घिरे हुए स्थान पर/ सुदूर क्षेत्र में स्थित हैं जिससे कि वे दृष्टिगोचर और प्रतिस्पर्धी बने रहें।

ड. अपनी रिफायनरियों में, फैक्ट्री के सेडों में संयंत्र और मशीनरियों में पर्याप्त पूंजी निवेश के बावजूद घरेलू खाद्य तेल उद्योगों की औसत स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ये उद्योग श्रम गहन भी हैं। घरेलू खाद्य क्षेत्रों के कार्य न करने के फलस्वरूप इस व्यापार में लगे लोगों के अतिरिक्त बेरोजगारी के खतरों के साथ-साथ उपभोक्ताओं की मांग को कम करने में गंभीर संकट पैदा होगा।

ग. महानिदेशक द्वारा जांच

14. इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अपने अनुरोधों में उपलब्ध कराई गई सूचना पर महानिदेशक द्वारा वर्तमान निर्धारण के उद्देश्य से विचार किया गया है और महानिदेशक निम्नलिखित नोट करते हैं:

ग.1 विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

15. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “परिष्कृत प्रक्षालित गंध रहित पामोलिव परिष्कृत प्रक्षालित गंध रहित पाम ऑयल” (क्रमशः आर बी डी पाम ऑयल और आर बी डी पामोलिन के रूप में भी जाना जाता है) है, जो सीमा प्रशुल्क अधिनियम के एच एस कोड 15119010 और 15119020 के अंतर्गत के आता है। आर बी डी पामालिन परिष्कृत प्रक्षालित और गंध रहित प्रकार का पाम ऑयल है जिसे पाम के फल की तराई करने के बाद निकाला जाता है। विचाराधीन उत्पाद का आमतौर पर उपयोग अस्वास्थ्य कर वसाओं जैसे नकली मक्खन, लघुकरण और वनस्पति घी का निर्माण करने के लिए किया जाता है।

ग.2 घरेलू उद्योग

16. इस नियमावली, 2017 के नियम 2(ख) में नीचे दिये गये अनुसार प्रावधान है :

“घरेलू उद्योग” का आशय

- (i) भारत में समान वस्तु अथवा प्रत्यक्ष रूप प्रतिस्पर्धी वस्तु के समग्र के रूप में आयात किये गये वस्तुओं, उत्पादकों के संबंध में है; अथवा
- (ii) जिसका भारत में समान वस्तु का सामूहिक उत्पादन भारत में ऐसी वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा अनुपात है।

17. इसके अलावा, आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में नियम 4 में नीचे दिये गये अनुसार प्रावधान है :

महानिदेशक समान वस्तु अथवा प्रत्यक्ष तौर पर प्रतिस्पर्धी वस्तु घरेलू उत्पादकों की ओर से अथवा उनके द्वारा लिखित आवेदन के प्राप्त होने पर व्यापार करार के अंतर्गत सीमा शुल्क में कमी अथवा उसकी समाप्ति के फलस्वरूप मूल वस्तु के बड़े हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति के होने अथवा हुई क्षति गंभीर क्षति के खतरे का निर्धारण करने के लिए जांच शुरू कर सकते हैं।

18. यह आवेदन भारत में “परिष्कृत प्रक्षालित गंध रहित पामोलिव परिष्कृत प्रक्षालित गंध रहित पाम ऑयल” के घरेलू उत्पादकों की ओर से साल्वेंट एक्ट्रेचर एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के द्वारा दायर किया गया है। इस याचिका में समग्र रूप में घरेलू उद्योग के लिए सूचना निहित है। इसकी घरेलू उत्पादकों ने विशेष रूप से द्विपक्षीय रक्षोपाय कदम को लागू किये जाने की मांग की है।

- क. 3एफ इंडस्ट्री लिमि.,
- ख. अदानी विलमर लिमि.,
- ग. सी ओ एफ सी ओ इंटरनेशनल,
- घ. इमामी एग्रोटेक लिमि.
- ङ. जेमिनी इडिब्ले फेट्स एंड ऑयल्स लिमि.
- च. गोकुल एग्रो रिसोर्सिस लिमि.,
- छ. लिबर्टी ऑयल मिल्स लिमि.,
- ज. ओजोन प्रोकाॅन प्रा. लिमि.,
- झ. रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमि. (6 यूनिट्स)

19. यह माना गया है कि इस याचिका को भारत में समान वस्तु के “समग्र रूप में घरेलू उत्पादकों” की ओर से दायर किया गया है और साल्वेंट एक्ट्रेचर एसोसिएशन ऑफ इण्डिया को इस जांच के, नियम 2 (ख) के संदर्भ, में उद्देश्य से घरेलू उद्योग के रूप में लिया गया है।

ग.3 जांच की अवधि (पीओआई)

20. यह अवधि जनवरी, 2019 से जून, 2019 को इस तथ्य के निर्धारण के उद्देश्य से जांच की अवधि (पी ओ आई) के रूप में मानी गई है कि क्या संबद्ध वस्तुओं के आयातों में इतनी मात्रा में वृद्धि हुई है जिससे कि यह “बढ़ा हुआ आयात”

माना जा सकता है। कच्चे पाम आयल और संबद्ध वस्तुओं लागू सीमा शुल्क ने 1 जनवरी, 2019 से परिवर्तन हुआ है। न तो घरेलू कानून और न ही गैट (जी ए टी टी) के रक्षोपाय करार और अनुच्छेद XIX और न ही इस नियमावली ने इस तथ्य को छोड़कर जांच की अवधि पर कई विशिष्ट दिशानिर्देश दिये गये हैं की संगत जांच की अवधि भारतीय उद्योग को गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति के खतरे तथा बढ़े हुए आयात पर निकाले जाने वाले निष्कर्ष की अनुमति देने के लिए पर्याप्त रूप से लंबी होनी चाहिए। क्षति की जांच की अवधि को 2016 - 17, 2017 - 18, अप्रैल - दिसंबर, 2018 और जांच की अवधि के रूप में माना गया है। अप्रैल - दिसंबर, 2018 और जांच की अवधियों के लिए वर्तमान जांच परिणाम में आंकड़ों का उल्लेख पिछले वर्ष की अवधि के प्रयोग किये जाने के उद्देश्य से वार्षिकीकृत आधार पर किया गया है।

ग.4 सूचना का स्रोत

21. चूंकि संबद्ध वस्तुओं का समर्पित सीमा शुल्क कोड है अतः अप्रैल 2015 से जून 2019 तक की अवधि के लिए आयात संबंधी आंकड़ों पर वाणिज्यिक सूचना एवं सांख्यिकीय महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) द्वारा प्रकाशित आयात निर्यात आंकड़ों के अनुसार विचार किया गया है। गंभीर क्षति के संबंध में दी गयी सूचना पर विचार समग्र रूप से घरेलू उत्पादकों के लिए किया गया है।

22. गंभीर क्षति के संबंध में सूचना आवेदक द्वारा समग्र रूप में घरेलू उत्पादकों के संबंध में उपलब्ध कराई गई है। जांच की शुरुआत करने के बाद, महानिदेशक ने संघ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के अनुसार घरेलू उत्पादकों को प्रश्नावली जारी की जिसमें उन्हें निदेश दिया गया कि वे निर्धारित प्रश्नावली के अनुसार सूचना उपलब्ध करायें। निम्नलिखित घरेलू उत्पादकों द्वारा उक्त सूचना उपलब्ध कराई गई है :

- क. इमामी एगोटेक लिमि.
- ख. लिबर्टी ऑयल मिल्स लिमि.
- ग. जेमिनी इडिब्ले फेट्स एंड ऑयल्स लिमि.
- घ. अदानी विलमर लिमि.
- ङ. गोकुल एगो रिसोर्सिस लिमि.
- च. विमल ऑयल एंड फूड्स लिमि.
- छ. ओजोन प्रोकॉन प्रा. लिमि.

23. महानिदेशक ने निम्नलिखित आधार पर क्षति और गंभीर क्षति के उत्पन्न होने पर विचार किया है।

क. मानदंडों जैसे बाजार का हिस्सा, क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता का उपयोग, बिक्री का निर्धारण सबसे पहले घरेलू उत्पादकों के लिए समग्र रूप में किया गया है और उसके बाद भाग लेने वाली कंपनियों के लिए भी किया गया है।

ख. मानदंडों जैसे लाभ, मजदूरी और रोजगार की जांच समेकित आधार पर सभी घरेलू उत्पादकों के संबंध में की गई है। इन मानदंडों का विश्लेषण भी उत्तर देने वाले घरेलू उत्पादकों के संबंध में अलग अलग आधार पर किया गया है।

24. गंभीर क्षति के खतरे के कारण, महानिदेशक ने इस सूचना पर विचार किया है जो याचिकाकर्ता द्वारा अपने आवेदन में उपलब्ध कराई गई सूचना और जांच की शुरुआत किये जाने के बाद प्रस्तुत की गई अतिरिक्त सूचना है। आवेदक द्वारा जांच की शुरुआत किये जाने के बाद प्रस्तुत की गई सूचना की एक प्रति इन पक्षकारों के अवलोकन के लिये सार्वजनिक फाइल में रखी गई है जिससे कि वे अपनी टिप्पणियां यदि कोई हो, प्रस्तुत कर सकें जिस पर रक्षोपाय शुल्क के अंतिम निर्धारण के दौरान विचार किया जायेगा।

ग.5. सीईसीए के तहत सीमा शुल्क

25. मलेशिया की सरकार और (भारत की गणतांत्रिक सरकार) के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सी ई सी ए) सी ई सी ए (करार) और भारत- आशियन मुक्त व्यापार करार (ए आई एफ टी ए) ने नीचे किये गये उल्लेख के अनुसार सी पी ओ और आर बी डी पामोलिन पर सीमा शुल्क में कमी का प्रावधान किया :

सी ई सी ए अधिमन्य प्रशुल्क			
	प्रशुल्क लाइन	सी पी ओ	आर पी ओ
	आधार दर	80	90

	लागू प्रवेश (ईआईएफ)	72	82
के बाद नहीं	1.1.2012	68	78
	1.1.2013	64	74
	1.1.2014	60	70
	1.1.2015	56	66
	1.1.2016	52	62
	1.1.2017	48	58
	1.1.2018	44	54
	31.12.2018	40	45

	ए आई एफ टी ए अधिमान्य प्रशुल्क		
	प्रशुल्क लाइन्स	सी पी ओ	आर पी ओ
	आधार दर	80	90
के बाद नहीं	2010	76	86
	2011	72	82
	2012	68	78
	2013	64	74
	2014	60	70
	2015	56	66
	2016	52	62
	2017	48	58
	2018	44	54
	2019	40	50

26. यह नोट किया जा सकता है कि सी पी ओ और आर पी ओ के बीच सीमा शुल्क अंतर अप्रैल 2015 से दिसंबर, 2018 तक की अवधि के दौरान 10 प्रतिशत था। हालांकि, सीमा शुल्क के अंतर में 01.01.2019 से 5 प्रतिशत तक कमी आई। सीमा शुल्क अंतर में इस कमी के फलस्वरूप कच्चे पाम ऑयल के आयातों में परिणामी गिरावट के साथ संबद्ध आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है।

ग.6 आयातों में वृद्धि

27. इस नियमावली के नियम 2(घ) में नीचे दिए गए अनुसार प्रावधान है :

“बढ़े हुए आयात” का आशय मलेशिया से आयातों में चाहे वह स्वतंत्र रूप में हुआ हो अथवा घरेलू उत्पादन के सापेक्ष हुआ हो वृद्धि से है

28. नियमावली में इस तथ्य की जांच की जानी अपेक्षित है कि क्या विचाराधीन उत्पाद के आयातों में स्वतंत्र रूप में अथवा सापेक्ष रूप में ऐसी मात्रा में वृद्धि हुई है जिससे कि वह “बढ़ा हुआ आयात” माना जाये। नियमावली में भारत में स्वतंत्र रूप में और आयातों की तुलना में दोनों में, भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में इन आयातों का विश्लेषण अपेक्षित है। विचाराधीन उत्पाद के बढ़े हुए आयातों का विश्लेषण इस नियमावली के संबंध में किया गया है।

i. स्वतंत्र रूप में मलेशिया से आयात

29. आयातों की गति नीचे दी गई तालिका में दर्शायी गई है

क्र. सं.	अवधि	मात्रा (मी. ट.)		
		मलेशिया	अन्य देश	कुल आयात
1	2016-17	626,362	2,315,292	29,41,654
2	2017-18	376,136	2,308,482	26,84,618
3	2018-19	696,909	1,729,644	24,26,553
4	अप्रैल – दिसं. 2018 (वार्षिकीकृत)	271,099	1,986,498	22,57,597
5	जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)	2,596,225	725,210	33,21,435
तिमाही आधार पर आयात (मी. ट.)				
1	क्यू 1 18-19	97,239	470,534	5,67,773
2	क्यू 2 18-19	78,879	640,816	7,19,695
3	क्यू 3 18-19	27,206	378,524	4,05,730
4	क्यू 4 18-19	493,584	239,771	7,33,355
5	क्यू 1 18-19	804,528	122,834	9,27,362

30. विचाराधीन उत्पाद के आयातों में स्वतंत्र रूप में जांच की अवधि में बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि हुई है। जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के आयातों में अचानक तीव्र और अत्यधिक वृद्धि हुई है। मलेशिया से आयातों में वृद्धि हुई है और यह 2016-17 में 626,362 मी. ट. से बढ़कर जनवरी-जून, 2019 में 2,596,225 मी. ट. (वार्षिकीकृत आधार पर) हो गई है और इस प्रकार से यह 314 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। अन्य देशों से आयातों में गिरावट हुई है और यह 2016-17 में 2,315,292 मी. ट. से घटकर जनवरी-जून, 2019 (वार्षिकीकृत आधार पर) 7,25,210 मी. ट. हो गया है।

31. आयातों में तिमाही गति का विश्लेषण यह दर्शाता है कि अक्टूबर-दिसंबर, 2018 में आयात 27,206 मी. ट. था जो अचानक बढ़कर अप्रैल-जून, 2019 में 804,528 मी. ट. हो गया और इस प्रकार से यह लगभग 29 गुणा वृद्धि को दर्शाता है।

II. मलेशिया और अन्य देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में वृद्धि का हिस्सा

32. मलेशिया और अन्य देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के हिस्से को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है :

क्र. सं.	अवधि	आयातों में हिस्सा (%)	
		मलेशिया	अन्य देश
1	2016-17	21%	79%
2	2017-18	14%	86%
3	2018-2019	29%	71%
4	अप्रैल - दिसं. 2018	12%	88%
5	जांच की अवधि वार्षिकीकृत	78%	22%
तिमाही आधार पर आयात			

1	Q1 18-19	17%	83%
2	Q2 18-19	11%	89%
3	Q3 18-19	7%	93%
4	Q4 18-19	67%	33%
5	Q1 19-20	87%	13%

33. यह नोट किया जाता है कि 2016-17 में मलेशिया से विचाराधीन उत्पाद का आयात भारत में कुल आयातों का 21 प्रतिशत था। आयातों में मात्रा वही रही और भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल आयातों की तुलना में दिसंबर 2018 तक आयातों की मात्रा में कोई वास्तविक वृद्धि नहीं हुई। हालांकि, मलेशिया से आयातों के हिस्से में जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक वृद्धि हुई। मलेशिया से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक मात्रा में 78 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। मलेशिया से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के समग्र हिस्से में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में लगभग 4 गुणा तक वृद्धि हुई है।

iii. भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में आयातों में वृद्धि

34. भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में खपत वस्तुओं के आयातों की गति नीचे दी गई तालिका में दर्शायी गई है :

क्र.सं.	अवधि	मलेशिया से	भारतीय	भारतीय	निम्नलिखित की तुलना में	
		आयात	उत्पादन	खपत	आया (%)	
		मी. ट.	मी. ट.	मी. ट.	उत्पादन	खपत
1	2016-17	626,362	***	***	***	***
2	2017-18	376,136	***	***	***	***
3	2018-19	696,909	***	***	***	***
4	अप्रैल – दिसं. 2018 (वार्षिकीकृत)	271,099	***	***	***	***
5	जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)	2,596,225	***	***	***	***
6	क्यू1 18-19	97,239	***	***	***	***
7	क्यू2 18-19	78,879	***	***	***	***
8	क्यू3 18-19	27,206	***	***	***	***
9	क्यू4 18-19	493,584	***	***	***	***
10	क्यू1 19-20	804,528	***	***	***	***

35. यह नोट किया जाता है कि मलेशिया से आयात 2016-17 में भारत में उत्पादन और खपत का क्रमशः 15 प्रतिशत और 9 प्रतिशत हुआ था। हालांकि, मलेशिया के हिस्से में जनवरी-जून, 2019 में क्रमशः 54 प्रतिशत और 32 प्रतिशत का उछाल आया। इस प्रकार से आयातों ने उत्पादन और खपत की तुलना में आयातों में बहुत अधिक वृद्धि को दर्शाया है। वास्तव में, इस हिस्से में अप्रैल-जून 2019 की अवधि में 2 प्रतिशत और अक्टूबर-दिसंबर, 2018 की अवधि में 1 प्रतिशत से क्रमशः 75 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत तक उछाल आया। उत्पादन और खपत की तुलना में आयातों में वृद्धि को इतनी कम अवधि में तीव्र और बहुत अधिक माना गया है।

ग.7 गंभीर क्षति

36. गंभीर क्षति और गंभीर क्षति के खतरे की परिभाषा इस नियमावली के अंतर्गत नीचे दिये गये अनुसार दी गई है :

(ग) गंभीर क्षति का आशय घरेलू उद्योग की स्थिति बहुत अधिक समग्र हानि से है; और

(घ) गंभीर क्षति के खतरे का आशय उस गंभीर क्षति से है जो समस्त रूप से आसन्न है और जिसका निर्धारण तथ्यों के आधार पर और न कि केवल आरोप, अनुमान अथवा दूर की संभावना के आधार पर किया जायेगा।

37. इस प्रकार आयातों में वृद्धि ऐसी होनी चाहिए जिसके कारण घरेलू उद्योग की स्थिति में बहुत अधिक समग्र हानि होती हो

38. इस नियमावली के नियम 7-में आगे नीचे दिये गये अनुसार प्रावधान है :

र करने के बाद घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति अथवा बातों के साथ साथ निमचामहानिदेशक अन्य गंभीर बाद घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति के खतरे का निर्धारण करेंगे अर्थात्:-

(क) महानिदेशक परिमाण निर्धारित करने योग्य और वस्तुपरक प्रकृति के सभी संगत कारकों का मूल्यांकन करेंगे जिसका उस घरेलू उद्योग की स्थिति विशेष रूप से स्वतंत्र और सापेक्ष रूप में मूल वस्तु के आयातों में वृद्धि की दर और राशि, मूल वस्तु के बड़े हुए आयातों के द्वारा कब्जा किये गये घरेलू बाजार का हिस्सा, बिक्री, उत्पादन, उत्पादकता, क्षमता का उपयोग, लाभ और हानि और रोजगार स्तर में परिवर्तन पर प्रभाव पड़ता हो।

39. यह नोट किया जाता है कि उल्लिखित मानदंडों के मूल्यांकन में अलग अलग उद्योगों और स्थितियों की विशेषताओं पर विचार किया जाना आवश्यक है। इस कारण से महानिदेशक ने घरेलू उद्योग की स्थिति और वर्तमान मामले के तथ्यों के संबंध घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति की जांच की है। इस प्रकार से सभी उल्लिखित कारकों और किसी अन्य संगत कारकों की तकनीकी जांच के अलावा, यह आवश्यक है कि इस उद्योग की समग्र स्थिति का मूल्यांकन उन सभी कारकों को ध्यान में रखकर किया जाता है जिनका इस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो।

40. तदनुसार, गंभीर क्षति और गंभीर क्षति के खतरे का विश्लेषण करने में सभी कारकों जिनका उल्लेख नियमावली में किया गया है और अन्य कारकों जो गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति के खतरे का निर्धारण करने के लिए संगत हैं, पर विचार किया गया है। गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति के खतरे का निर्धारण इन सभी संगत कारकों जिनका उस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो, के आलोक में इस उद्योग की समग्र स्थिति के मूल्यांकन पर आधारित है।

41. नियम 3 (ख) में नीचे दिये गये अनुसार है

महानिदेशक परिमाण निर्धारित करने योग्य और वस्तुपरक प्रकृति के सभी संगत कारकों का मूल्यांकन करेंगे जिसका उस घरेलू उद्योग की स्थिति विशेष रूप से स्वतंत्र और सापेक्ष रूप में मूल वस्तु के आयातों में वृद्धि की दर और राशि, मूल वस्तु के बड़े हुए आयातों के द्वारा कब्जा किये गये घरेलू बाजार का हिस्सा, बिक्री, उत्पादन, उत्पादकता, क्षमता का उपयोग, लाभ और हानि और रोजगार स्तर में परिवर्तन पर प्रभाव पड़ता हो।

42. संबद्ध वस्तुओं के बड़े हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति और गंभीर क्षति के खतरे की जांच इस नियमावली के अंतर्गत यथासूचीबद्ध निम्नलिखित कारकों का मूल्यांकन कर किया गया है :

i. स्वतंत्र और सापेक्ष रूप में आयातों में वृद्धि

43. यह नोट किया गया है कि संबद्ध वस्तुओं के आयातों में हाल की अवधि में स्वतंत्र रूप में तथा सापेक्ष रूप में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। इसके अलावा, आयातों में वृद्धि को नोट किया जाता है कि क्या इस स्थिति की तुलना 2016-17 और जनवरी – जून, 2019 अथवा तीव्र वृद्धि की अवधि के ठीक पूर्व की अवधि से की जा सकती है। यह भी नोट किया जाता है कि पिछले तिमाही की तुलना में अप्रैल – जून, 2019 में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी।

ii. उत्पादन और बिक्री

44. आवेदक ने अनुरोध किया है कि उत्पादन का एकमात्र स्रोत या तो घरेलू अथवा आयात किया गया कच्चा माल है और केवल कच्चे माल का उपयोग विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में होता है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि उत्पादक फूल को तोड़ने से लेकर तेल की खपत के चरण तक प्रत्येक चरण में इस उत्पाद के भंडारण और उपयोग होने की अवधि कम होने के कारण लंबे समय तक न तो कच्चे माल के भंडार को रख सकते हैं अथवा तैयार उत्पाद के भंडार को रख सकते हैं। याचिकाकर्ता का यह भी तर्क था कि कच्चे माल से उत्पाद के उत्पादन के लिए खपत मानदंड न केवल उचित रूप से सब्सिडीयुक्त है बल्कि इन्हें वैश्विक रूप से भी एक जैसा माना जा सकता है। याचिकाकर्ता ने सतत पाम ऑयल पर राउंड टेबल से संगत सामग्री भी प्रस्तुत की है जिसमें सी पी ओ और आर बी डी ऑयल के बीच इनपुट – आउटपुट अनुपात

दर्शाया गया है। याचिकाकर्ता ने यह भी अनुरोध किया है कि बिक्री उसी स्तर पर मानी जा सकती है जिस तरह से उत्पादन है चूंकि इस उत्पाद को लंबे समय तक भंडार में नहीं रखा जा सकता है।

45. उपर्युक्त को देखते हुए, सकल भारतीय उत्पादन और घरेलू बिक्री का आकलन इस प्रकार के खपत मानदंडों पर विचार करते हुए किया गया है इस उद्देश्य से, कच्चे माल की खपत अर्थात् सी पी ओ ेपर भारत में सी पी ओ के आयातों के आधार पर विचार किया गया है जो सार्वजनिक रूप से डी जी सी आई एंड एस द्वारा सूचित किया गया है।

46. उपर्युक्त पद्धति को अपनाते हुए घरेलू उत्पादन और बिक्री नीचे दिये गये अनुसार है :

क्र. सं.	अवधि	उत्पादन/ बिक्री	मांग
		मी. ट.	मी. ट.
1	2016-17	***	7,190,365
2	2017-18	***	7,995,216
3	2018-19	***	7,510,304
4	अप्रैल – दिसं. 18 वार्षिकीकृत	***	7,237,288
5	जांच की अवधि वार्षिकीकृत	***	8,174,382

47. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान मांग में वृद्धि हुई जबकि भारतीय उत्पादन और बिक्री में अप्रैल-दिसंबर, 2018 तक वृद्धि हुई तथा उसक बाद जांच की अवधि में गिरावट हुई है। भारतीय उत्पादन/ वृद्धि अप्रैल, 2018 से – दिसंबर, 2018 में *** मी. ट. थी जो घटकर जांच की अवधि में *** मी. ट. हो गयी अर्थात् इसमें 2.4 प्रतिशत से अधिक गिरावट हुई।

iii. क्षमता का उपयोग

48. क्षमता और क्षमता का उपयोग के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :

अवधि	क्षमता	क्षमता का उपयोग
	मी.ट	%
2016-17	13,900,000	***
2017-18	13,900,000	***
2018-19	13,900,000	***
अप्रैल-दिसं.'18	13,900,000	***
पीओआई	13,900,000	***

अवधि	क्षमता (मी. ट.)	क्षमता का उपयोग	उत्पादन की मात्रा (मी. ट.)
2016- 17	1,39,00,000	***	***
2017-18	1,39,00,000	***	***
2018-19	1,39,00,000	***	***
2019-20 (क्यू 1)	1,39,00,000	***	***
क्यू 1 17-18	34,75,000	***	***
क्यू 2 17-18	34,75,000	***	***

क्यू 3 17-18	34,75,000	***	***
क्यू 4 17-18	34,75,000	***	***
क्यू 1 18-19	34,75,000	***	***
क्यू 2 18-19	34,75,000	***	***
क्यू 3 18-19	34,75,000	***	***
क्यू 4 18-19	34,75,000	***	***
क्यू 1 19-20	34,75,000	***	***
अप्रैल-दिसं.'18	1,04,25,000	***	***
पीओआई जन.-जून'19	69,50,000	***	***

49. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता का बहुत कम उपयोग किया है और उनकी क्षमता का उपयोग जांच की अवधि के दौरान कम हो गया है।

iv. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा

50. बाजार हिस्से की गति नीचे दी गई है :

क्र. सं.	अवधि	बाजार हिस्सा (%)	
		मलेशिया	भारतीय उद्योग
2	2016-17	9%	59%
3	2017-18	5%	66%
4	2018-19	9%	68%
5	अप्रैल – दिसं. '18	4%	69%
6	जांच की अवधि	32%	59%
7	जन. - मार्च, 2019	24%	65%
8	अप्रैल - जून, 2019	40%	54%

51. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है जबकि मलेशिया से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के बाजार हिस्से में पूर्व की वर्षों में तुलना में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

v. रोजगार और उत्पादकता

52. आवेदक ने यह दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के प्रसंस्करण में लगाये गये मानव घंटों में वर्तमान अवधि में बहुत अधिक गिरावट आई है और *** लाख तक उत्पादन/ बिक्री की वार्षिक हानि पर विचार करते हुए (अक्टूबर – दिसंबर 2018 और जांच की अवधि में बिक्री पर विचार करते हुए) इस उत्पाद के लिए लगाये गये रोजगार में लगभग *** तक गिरावट आई है। इस तथ्य को देखते हुए कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में गिरावट हुई है, उत्पादकता में गिरावट हुई है।

vi. लाभ/ हानि

53. आयात किये गये कच्चे परिष्कृत तेल से परिवर्तन के बाद संबद्ध वस्तुओं की लागत एवं इसकी उचित नीचे दिये गये हैं :

	इकाई	जांच की अवधि वार्षिकीकृत
कच्ची आयात मात्रा	मी. ट.	***
आयात मूल्य रु.लाख	रु. लाख	***
सी आई एफ रु./ मी. ट.	रु./ मी. ट.	***
सीमा शुल्क %	%	***
सीमा शुल्क राशि	रु./ मी. ट.	***
उपकर राशि	रु./ मी. ट.	***
पहुंच लगात	रु./ मी. ट.	***
खपत कारक		***
आर एम लागत	रु./ मी. ट.	***
घटायें : उत्पाद से	रु./ मी. ट.	***
परिवर्तन लागत	रु./ मी. ट.	***
पाम ऑयल का शुद्ध मूल्य	रु./ मी. ट.	***
लाभ	5%	***
उचित कीमत	रु./ मी. ट.	***

54. उपर्युक्त उचित कीमत की तुलना में, मलेशिया से जांच की अवधि में आयात किये गये आर बी डी पामोलिन की पहुंच कीमत नीचे दिये गये अनुसार है :

विवरण	यूओएम	राशि
मात्रा (मी. ट.)	मी.ट.	2,596,225
सी आई एफ दर	रु./ मी. ट.	40,997
सीमा शुल्क	%	45%
सीमा शुल्क राशि	रु./ मी. ट.	18,449
उपकर राशि	रु./ मी. ट.	553
आर बी डी पामोलिन की पहुंच कीमत	रु./ मी. ट.	60,000

55. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उत्पादकों ने स्वयं आर बी डी पामोलिन का आयात करना शुरू किया जिससे कि वे बाजार में बने रहे सकें। इसके परिणामस्वरूप, घरेलू उत्पादकों को बहुत अधिक उत्पादन और उसके परिणामस्वरूप बिक्री की हानि हुई है। इसके फलस्वरूप घरेलू उत्पादकों को लाभ में बहुत अधिक हानि हुई है। 1500 रु. प्रति पी एम टी के उचित लाभ पर विचार करते हुए, घरेलू उद्योग की अनुमानित लाभप्रदता में इस अवधि के दौरान बहुत अधिक गिरावट आई जिसे निम्नलिखित से नोट किया जाता है :

	बिक्री	लाभ
	मी. ट.	रु. करोड़
2016- 17	42,47,839	***
2017-18	53,08,775	***

क्यू1 18-19	9,52,452	***
क्यू2 18-19	12,69,789	***
क्यू3 18-19	15,01,645	***
क्यू4 18-19	13,46,697	***
क्यू1 19-20	10,77,169	***

56. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के अनुमानित लाभ में जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक गिरावट आई।

vii. कीमत ह्रास/ न्यूनीकरण और कीमत में कटौती

57. संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत की तुलना संबद्ध वस्तुओं के लिए तय की गई उचित कीमत से तुलना नीचे दी गई तालिका में दर्शायी गई है :

विवरण	इकाई	लागत
आर बी डी पाम ओलिन की उचित कीमत	रु./ मी. ट.	***
आर बी डी पामोलिन की पहुंच कीमत	रु./ मी. ट.	***
अंतर	रु./ मी. ट.	***

58. यह नोट किया जाता है कि आर बी डी पामोलिन की पहुंच कीमत घरेलू उत्पादकों द्वारा अपेक्षित आर बी डी पामोलिन की उचित कीमत के स्तर से बहुत कम है, यदि वे सी पी ओ का आयात करें और उसे आर बी डी पामोलिन में प्रसंस्कृत करें। यह दर्शाता है कि इन आयातों के कारण घरेलू उत्पादकों की कीमतों पर उस सीमा तक दबाव पड़ रहा है कि घरेलू उत्पादक उस सीमा तक उत्पादन क्रियाकलाप ही नहीं कर रहे हैं। आयातों की पहुंच कीमत और उचित कीमत के बीच अंतर बहुत अधिक है जो मलेशिया से संबद्ध वस्तुओं के आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती को दर्शाता है।

ग.8 घरेलू उत्पादकों जिन्होंने आंकड़े उपलब्ध कराये हैं का क्षति विश्लेषण

59. समग्र रूप में घरेलू उत्पादकों के संबंध में इस उद्योग के कार्य निष्पादन के विश्लेषण के अलावा, महानिदेशक ने उन कंपनियों के कार्य निष्पादन का विश्लेषण किया है जिन्होंने जांच की शुरुआत के बाद सूचना उपलब्ध कराई। निम्नलिखित घरेलू उत्पादकों ने क्षमता, उत्पादन, बिक्री, रोजगार, मजदूरी, उत्पादकता और लाभ से संबंधित सूचना उपलब्ध कराई है।

- क. इमामी एग्रोटेक लिमि.
- ख. लिबर्टी ऑयल मिल्स लिमि.
- ग. जेमिनी इडिब्ले फेट्स एंड ऑयल लिमि.
- घ. अदानी विलमर लिमि.
- ङ. गोकुल एग्रो रिसोर्सिस लिमि.
- च. विमल ऑयल एंड फूड्स लिमि.
- छ. ओजोन प्रोकॉन प्रो. लिमि.

60. याचिका और बाद की प्रस्तुतियों से यह नोट किया जाता है कि इन कंपनियों का उत्पादन और बिक्री दिसंबर 2018 तक बढ़ रही थी। हालांकि, उत्पादन और बिक्री में 23 प्रतिशत (जांच की अवधि) और 31 प्रतिशत (अप्रैल – जून, 2019) तक गिरावट आई है। उत्पादन और बिक्री में गिरावट बहुत अधिक मानी गई है। इसके परिणामस्वरूप, इन कंपनियों के क्षमता के उपयोग और लाभ में भी बहुत अधिक गिरावट आई है। रोजगार और मजदूरी अधिकांश रूप में एक जैसी रही है। हालांकि उत्पादकता में बहुत अधिक गिरावट आई।

61. अलग अलग कंपनियों के कार्य निष्पादन की भी जांच उसी अवधि के लिए की गई है। यह नोट किया जाता है कि इन कंपनियों में से अधिकांश कंपनियों का उत्पादन, उत्पादकता और बिक्री दिसंबर 2018 तक बढ़ रही थी और इसमें जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक गिरावट आई।

	उत्पादन (तिमाही) (मी.ट. में)						
	जेमिनी	ओजोन	गोकुल	इमामी	अदानी	लिबर्टी	विमल
2016- 17	***	***	***	***	***	***	***
2017-18	***	***	***	***	***	***	***
क्यू 1 18-19	***	***	***	***	***	***	-
क्यू 2 18-19	***	***	***	***	***	***	-
क्यू 3 18-19	***	***	***	***	***	***	-
क्यू 4 18-19	***	***	***	***	***	***	-
क्यू 1 19-20	***	***	***	***	***	***	-

	क्षमता का उपयोग (% में)						
	जेमिनी	ओजोन	गोकुल	इमामी	अदानी	लिबर्टी	विमल
2016- 17	***	***	***	***	***	***	***
2017-18	***	***	***	***	***	***	***
क्यू 1 18-19	***	***	***	***	***	***	***
क्यू 2 18-19	***	***	***	***	***	***	***
क्यू 3 18-19	***	***	***	***	***	***	***
क्यू 4 18-19	***	***	***	***	***	***	***
क्यू 1 19-20	***	***	***	***	***	***	***

	प्रति दिन उत्पादकता (मी. ट. में)						
	जेमिनी	ओजोन	गोकुल	इमामी	अदानी	लिबर्टी	विमल
2016- 17	***	***	***	***	***	***	***
2017-18	***	***	***	***	***	***	***
क्यू 1 18-19	***	***	***	***	***	***	-
क्यू 2 18-19	***	***	***	***	***	***	-
क्यू 3 18-19	***	***	***	***	***	***	-
क्यू 4 18-19	***	***	***	***	***	***	-
क्यू 1 19-20	***	***	***	***	***	***	-

	उत्पादन (सूचीबद्ध)						
	जेमिनी	ओजोन	गोकुल	इमामी	अदानी	लिबर्टी	विमल
2016- 17	100	100	100	100	100	100	100

2017-18	193	1,747	145	124	111	173	40
क्यू 1 18-19	351	1,949	58	86	94	50	-
क्यू 2 18-19	301	2,159	86	117	105	46	-
क्यू 3 18-19	415	2,869	201	149	150	145	-
क्यू 4 18-19	368	2,360	91	131	124	202	-
क्यू 1 19-20	330	762	66	116	87	212	-
क्षमता उपयोग (सूचीबद्ध)							
	जेमिनी	ओजोन	गोकुल	इमामी	अदानी	लिबर्टी	विमल
2016- 17	100	100	100	100	100	100	100
2017-18	193	1,747	145	124	111	173	40
क्यू 1 18-19	351	1,949	58	86	94	50	-
क्यू 2 18-19	301	2,159	86	117	105	46	-
क्यू 3 18-19	415	2,869	201	149	150	145	-
क्यू 4 18-19	368	2,360	91	131	124	202	-
क्यू 1 19-20	330	762	66	116	87	212	-
प्रति दिवस उत्पादकता (सूचीबद्ध)							
	जेमिनी	ओजोन	गोकुल	इमामी	अदानी	लिबर्टी	विमल
2016- 17	100	100	100	100	100	100	100
2017-18	193	1,747	145	124	111	173	40
क्यू 1 18-19	351	1,949	58	86	94	50	-
क्यू 2 18-19	301	2,159	86	117	105	46	-
क्यू 3 18-19	415	2,869	201	149	150	145	-
क्यू 4 18-19	368	2,360	91	131	124	202	-
क्यू 1 19-20	330	762	66	116	87	212	-

ग.9 क्षति संबंधी निष्कर्ष

62. इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों में स्वतंत्र रूप में और भारत में सकल आयातों, भारतीय उत्पादन और खपत की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। मलेशिया से आयातों में अचानक बहुत अधिक वृद्धि के फलस्वरूप, घरेलू उत्पादकों को उत्पादन, बिक्री, क्षमता का उपयोग, बाजार हिस्से, लाभ में उस उत्पाद के लिए प्रसंस्करण क्रिया कलाप और प्रसंस्करण के लिए तैनात मानव शक्ति में बहुत अधिक गिरावट के संबंध में गंभीर क्षति हुई है। विभिन्न मानदंडों के संबंध में घरेलू उत्पादकों के कार्य निष्पादन पर विचार करते हुए, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि घरेलू उद्योग को मलेशिया से विचाराधीन उत्पाद के बढ़े हुए आयातों के फलस्वरूप गंभीर क्षति हुई है।

ग.10. कारणात्मक संबंध

63. इन मानदंडों जिनका ऊपर में एक एक करके उल्लेख किया गया है, का व्यापक मूल्यांकन यह दर्शाता है कि गंभीर क्षति जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं बढ़े हुए आयातों के कारण हो रहे थे। कारणात्मक कार्य

संबंध का निर्धारण करने के उद्देश्य से, यह वस्तुपरक और मात्रा निर्धारित करने योग्य प्रकृति के सभी संगत कारकों जिसका उद्योग की इस स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो, का मूल्यांकन किया गया है। वर्तमान मामले में, इस संबंध में निम्नलिखित बिंदु संगत हैं --

- क. विचाराधीन उत्पाद के आयातों में जांच की अवधि में स्वतंत्र रूप से तथा सापेक्ष रूप में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी।
- ख. घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से में कमी आई थी जबकि मलेशिया से आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई थी।
- ग. आयात की पहुंच कीमत जांच की अवधि में संबद्ध वस्तुओं की उचित कीमत की तुलना में पर्याप्त रूप से कम थी।
- घ. घरेलू उत्पादक बाजार में अपनी मौजूदगी को बनाये रखने के उद्देश्य से इन वस्तुओं का आयात करने के लिए बाध्य थी।
- ड. घरेलू उत्पादकों की बिक्री, उत्पादन, क्षमता का उपयोग, तैनात मानव शक्ति और लाभ में जांच की अवधि में बढ़े हुए आयातों के फलस्वरूप गिरावट आई थी।

64. इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग की क्षति जांच की अवधि के दौरान बढ़े हुए आयातों के कारण हुई थी और मलेशिया से संबद्ध वस्तुओं के बढ़े हुए आयातों और घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति तथा गंभीर क्षति के खतरे के बीच कारणात्मक संबंध था।

ग.11. गंभीर क्षति का खतरा

65. इस नियमावली में नीचे दिये गये अनुसार प्रावधान है :

“गंभीर क्षति के खतरे” का आशय उस गंभीर क्षति से है जो स्पष्ट रूप से आसन्न है और जिसका निर्धारण तथ्यों और न केवल आरोप, अनुमान अथवा दूर की संभावना के आधार पर किया जायेगा।

66. यह नोट किया जाता है कि मलेशिया से सतत वस्तुओं का आयात भारतीय बाजार में स्वतंत्र रूप में तथा भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में बहुत अधिक बढ़ी हुई मात्राओं में हो रहा है। घरेलू उद्योग की क्षमता का कम उपयोग किया गया था और मलेशिया से अत्यधिक आयातों के कारण इस स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पहुंच कीमत और संबद्ध वस्तुओं की उचित कीमत के साथ-साथ प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए जाने के समय दर्शाए गए मलेशिया में निर्यात उन्मुख उत्पादकों के पास काफी मात्रा में क्षमताओं के तथ्य के साथ बीच के अंतर पर मलेशिया के पास बहुत अधिक मात्रा में क्षमताओं के साथ साथ उनके अत्यधिक निर्यात उन्मुखीकरण का तथ्य यह दर्शाता है कि मलेशिया से संबद्ध वस्तु संभवतः लाभप्रद रहेंगे, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति का लगातार खतरा बना रहेगा। हलांकि, चूंकि संबद्ध वस्तुओं के आयातों को दिनांक 8 जनवरी, 2010 की अधिसूचना सं. 39/ 2015-2020 की अधिसूचना के मध्यम से “प्रतिबंधित श्रेणी” के अंतर्गत रखा गया है और इस तथ्य के कारण भी कि कच्चे पाम तेल और संबद्ध वस्तुओं के बीच शुल्क में अंतर सीईसीए और आशियान दोनों करारों के अंतर्गत 7.5 प्रतिशत हो गया है, यह नोट किया जाता है कि सी ई सी ए के अंतर्गत मलेशिया से आयातों के कारण घरेलू उद्योग का आगे कोई खतरा नहीं है, प्रतीत होता है।

घ. निष्कर्ष

67. यह नोट किया जाता है कि वर्तमान मामले के संबंध में नाजुक परिस्थितियों की जांच करने के बाद, प्राधिकारी अनंतिम रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि घरेलू उद्योग द्वारा उठाई जा रही क्षति मलेशिया से संबद्ध वस्तुओं के गहन और बढ़े हुए आयातों के कारण हुई थी और उन्होंने दिनांक 26 अगस्त, 2019 की अधिसूचना सं. 22/4/2019 के माध्यम से 180 दिन की अवधि के लिए अनंतिम शुल्क की सिफारिश की थी। केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 4 सितंबर, 2019 की अधिसूचना सं. 29/2019 –सीमाशुल्क के माध्यम से अनंतिम शुल्क लगाया और उप प्रशुल्क 2 मार्च, 2020 तक लागू है।

68. इस बीच जब जांच चल रही थी, सरकार ने एच एस कोड 151190 10 के अंतर्गत मदों (परिष्कृत प्रच्छालित गंध रहित पाम ऑयल, एच एस कोड 151190 20 (परिष्कृत प्रच्छालित गंधरहित पामोलिन) और (एच एस कोड 1511 909 0 (अन्य) की आयात नीति में दिनांक 8 जनवरी, 2010 की अधिसूचना सं. 39/2015-2020 के माध्यम से संशोधन किया और इस प्रकार से इन संबद्ध वस्तुओं को “प्रतिबंधित श्रेणी” के अंतर्गत रखा गया। घरेलू उद्योग द्वारा यह भी ध्यान में लाया गया है कि आशियान करार (जिसमें मलेशिया शामिल है) और सी ई सी ए करार के अंतर्गत मूल सीमाशुल्क में भी 1 जनवरी, 2020 से परिवर्तन हुआ है। अब, कच्चे पाम ऑयल और परिष्कृत पामोलिन/पॉम ऑयल के बीच अंतर इन दोनों करारों में 7.5 प्रतिशत है। यह भी अनुरोध किया गया है कि जबकि कच्चे और परिष्कृत पाम ऑयल

के बीच अंतर घरेलू उत्पादकों के सतत प्रचालनों के लिए पर्याप्त नहीं है, किसी भी स्थिति में इन दोनों करारों के अंतर्गत सीमाशुल्क अब एक है। इस कारण से आशियान करार के अंतर्गत समान शुल्क के बिना वर्तमान में रक्षोपाय शुल्क का मतलब एक निरर्थक रक्षोपाय शुल्क होगा क्योंकि उपभोक्ता आशियान करार के अंतर्गत लाभ प्राप्त करेंगे। यह भी अनुरोध किया गया है कि चूंकि संबद्ध वस्तुओं का आयात अब प्रतिबंधित सूची के अंतर्गत है, अतः यह उत्पाद अब विनियमित रहेगा। हल के इन घटनाक्रमों को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि 180 दिन से आगे रक्षोपाय शुल्क लगाना आवश्यक नहीं हो सकता है।

69. उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुए यह माना गया है कि सी ई सी ए के अंतर्गत परिष्कृत प्रच्छालित गंध रहित पाम आयल आर “परिष्कृत प्रच्छालित गंध रहित पमोलिन” के आयात पर रक्षोपाय शुल्क 180 दिनों की अवधि के लिए अनंतिम झूटी लगाना 4 सितंबर, 2019 की अधिसूचना संख्या 29/2019-सीमा शुल्क के अनुसार, वर्तमान में पर्याप्त है

ड. सिफारिशें

70. अतः दिनांक 26 अगस्त, 2019 की अधिसूचना सं. 22/4/2019 के माध्यम से जारी किए गए प्रारंभिक जांच परिणाम की पुष्टि की जाती है। महानिदेशक दिनांक 4 सितंबर, 2019 की अधिसूचना सं. 29/2019-सीमा शुल्क के माध्यम से जारी की गई केन्द्र सरकार द्वारा अनंतिम शुल्क लगाए जाने की तिथि से 180 दिनों की अवधि के लिए “परिष्कृत प्रच्छालित गंध रहित पाम ऑयल” और “परिष्कृत प्रच्छालित गंध रहित पमोलिन” के आयात पर सी ई सी ए के अंतर्गत दिनांक 26 अगस्त, 2019 की अधिसूचना सं. 22/4/2019 के माध्यम से जारी किए गए प्रारंभिक जांच परिणामों में उल्लिखित रूप में और तरीके से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर द्विपक्षीय रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं।

71. पूर्व में रिकॉर्ड किए गए कारणों को देखते हुए, महानिदेशक, द्विपक्षीय रक्षोपाय शुल्क के आगे विस्तार की सिफारिश नहीं करते हैं।

भूपिन्दर एस. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Trade Remedies)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February 2020

(Bilateral Safeguard Investigation)

[Case No: (SG) 04/2019]

Final Findings

Subject: Final findings of Bilateral Safeguard Investigation concerning imports of “Refined Bleached Deodorised Palmolein and Refined Bleached Deodorised Palm Oil” into India from Malaysia under India-Malaysia Comprehensive Economic Cooperation Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017

F. No. 22/4/2019-DGTR.—Having regard to the Article 5 of the Comprehensive Economic Cooperation Agreement (CECA) between the Government of the Republic of India and the Government of Malaysia and India-Malaysia Comprehensive Economic Cooperation Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017 thereof.

A. Procedure

1. An application had been filed under India-Malaysia Comprehensive Economic Cooperation Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017 (hereinafter also referred to as the “Rules” or “bilateral safeguard rules”) by the Solvent Extractors’ Association (SEA) of India on behalf of the Indian domestic producers, alleging increased imports of “Refined Bleached Deodorised Palm Oil” and “Refined Bleached Deodorised Palmolein” (hereinafter also referred to as the “product under consideration” or “PUC” or “subject goods”) from Malaysia (also referred to as subject

- country) causing serious injury and threat of serious injury to the domestic producers of like or directly competitive product in India.
2. Having satisfied that the requirements of Article 4 of Bilateral Safeguard Rules were met, a Bilateral safeguard investigation into increased imports of “Refined Bleached Deodorised Palm Oil” (RBD Palm Oil) and “Refined Bleached Deodorised Palmolein”(RBD Palmolein) from Malaysia was initiated vide notice of initiation dated 14th August, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary. Interested parties were requested to make their views known in writing within 30 days of the initiation notice.
 3. Questionnaire was sent to the following foreign producers of the product in Malaysia:
 - i. Felda Marketing Services Son Bhd
 - ii. Golden Jomalina Food Industries Son Bhd
 - iii. 101 Edible Oils Son Bhd
 - iv. Kl-Kepong Edible Oils Son Bhd
 - v. Mewaholeo Industries Son Bhd
 - vi. Ngo Chew Hong Oils & Fats (M) Son
 - vii. Southern Edible Oil Industries (M) Son
 - viii. Kwantas Oil Son Bhd
 - ix. Sarawak Oil Palm Berhad
 - x. Siam Derby Oils Langat Refinery
 - xi. Golden Agri Resources Ltd
 - xii. Wilmar International
 4. Following parties have submitted questionnaire responses:
 - i. SOP Edible Oils Sdn. Bhd
 - ii. Sime Darby Oils Bintulu Sdn Bhd
 - iii. Borneo Edible Oils Sdn Bhd
 5. Domestic industry questionnaire was sent to the Applicant association directing them to provide information as per prescribed format. The following domestic producers provided the information related to injury parameters.
 - i. Emami Agrotech Ltd
 - ii. Liberty Oil Mills Ltd.
 - iii. Gemini Edible Fats & Oils Ltd
 - iv. Adani Wilmar Ltd.
 - v. Gokul Agro Resources Ltd
 - vi. Vimal Oil & Foods Ltd
 - vii. Ozone Procon Pvt Ltd
 6. The following importers have submitted importer questionnaire response/submissions in the investigation:
 - i. Budge Budge Refineries Ltd
 - ii. RSH Agro Products ltd
 - iii. Figorifico Allana Private Ltd

7. The request made by the domestic industry for imposition of provisional safeguard duty was examined and it was provisionally determined that critical circumstances existed which warranted imposition of provisional safeguard duty in order to provide interim relief to the domestic industry from suffering the damage, which could have been difficult to repair. Accordingly, the Preliminary Findings recommending provisional duty was issued under Rule 9 (2) of the Rules vide Notification No. 22/4/2019 dated 26th August, 2019. The Central Government imposed the provisional duty vide notification No. 29/2019-Customs dated 4th September, 2019.
8. An oral hearing was held on 21st October 2019 in terms of Rule 5(6) of the Rules. The interested parties, namely, the Domestic Industry and the Government of Malaysia, attended the hearing and made oral submissions. Due to change in the incumbency of the Director General, another oral hearing was conducted by the present Director General (DG) on 11th December, 2019 in pursuance of the direction given in the judgment delivered by the Hon'ble Supreme Court in the matter of Automotive Tyre Manufacturers' Association (ATMA) Vs the Designated Authority in Civil Appeal 949 of 2006.
9. Copy of written submissions filed post oral hearing by interested parties were made available to all the other interested parties. Interested parties were also given an opportunity to file rejoinders, if any, to the written submissions of other interested parties.
10. All the views expressed by the interested parties were examined and have been taken into account in making appropriate determination. The non-confidential version of the information received has been kept in the public file.

B. Submissions made by Interested parties during the course of investigation

Views of the Applicant

11. Submissions made by the domestic industry are as follows:

- a. Application for safeguard measures under the Agreement has been filed by Solvent Extractors' Association of India and therefore it should be considered that the application has been filed on behalf the producers of "Refined Bleached Deodorised Palm Oil" and "Refined Bleached Deodorised Palmolein" in India.
- b. The product under investigation (PUC) is "Refined Bleached Deodorised Palm Oil" and "Refined Bleached Deodorised Palmolein" (also known as RBD Palm Oil and RBD palmolein, respectively), falling under the HS code 15119010 and 15119020.
- c. Product under consideration is commonly used to formulate trans-free fats such as margarine, shortening and vegetable ghee.
- d. There are various producers who are member of the association and nine of them have supported the petition.
- e. The association does not maintain individual producer's data such as production, sales, stocks, profits, etc. in view of the fact that this is commercially sensitive data and the association is constrained not to undertake this activity in view of Competition laws in the Country.
- f. Information on domestic production has been derived from two sources :
 - a. from domestic crude palm oil (CPO) production,
 - b. from imported crude palm oil.
- g. The Applicant has derived gross Indian production by applying the conversion factor from Crude Palm Oil to subject goods considering that one MT raw material (CPO) produces 0.95 MT Refined palm oil and one MT refined palm oil produces 0.80 MT RBD Palmolein.
- h. Palm oil is semi-solid at room temperature (20°C). The liquid portion could be physically separated from the solid portion of palm oil by fractionation. After fractionation the liquid

portion is called “palm olein” which is commonly bottled and sold as cooking oils. The solid fat portion is called “palm stearin” which is not under the scope of the product under consideration.

- i. The standard rate applicable on subject goods is 100%. However, the applied rate are low due to Preferential Custom Duty under Preferential Tariff Agreements (CECA with Malaysia) & (AIFTA), which were notified vide Notification No. 82/2018 & 84/2018 both dated 31.12.2018. The applied rate of custom duty have been much below the level of rates provided for in the AIFTA and CECA Agreement and the difference between the custom duty for CPO and subject goods was 10%. The applied rates increased significantly in March 2018. It was only after this that the custom duty rates applicable under CECA and ASEAN became relevant.
- j. The Applicant has filed this application pursuant to the Comprehensive Economic Cooperation Agreement entered into by Malaysia and Indian Government (CECA).
- k. Pursuant to CECA, the duty on imports of Crude Palm Oil (raw material of subject goods) from Malaysia has been reduced to 40% whereas the duty on subject goods has been reduced to 45%, vide Notification No. 82/2018 dated 31.12.2018. Thus, the difference between the duty on Crude Palm Oil and subject goods is a mere 5%.
- l. The difference between duty on Crude Palm Oil and subject goods have always been 10%. Following the reduction of duty difference from 10% to 5% between Crude Palm Oil and subject goods, imports from Malaysia of subject goods have increased significantly.
- m. There is significant increase in the import volumes in the POI. The imports have increased by 516% from 2015-16 to the POI. Imports of product concerned into India increased significantly in absolute terms and in relation to production, consumption and share in imports.
- n. The imports in relation to production and consumption have also increased significantly. Imports constituted 8% of share in Indian production in 2015-16 which increased to 73% in the POI. Similarly, imports constituted 5% of share in Indian consumption in 2015-16 which increased to 32% in the POI.
- o. Imports from Malaysia which constituted merely 17% of total Indian imports in 2015-16 increased to 78% of the total Indian imports in the proposed POI.
- p. Imports into India are largely from Indonesia and Malaysia. But Malaysia has duty advantage for RBD Palmolein under India – Malaysia CECA, so the country is now flooded with subject goods from Malaysia.
- q. Like product being produced by the domestic industry is the same as the imported product, i.e., “Refined Bleached Deodorised Palm Oil” and “Refined Bleached Deodorised Palmolein”. The domestic product is comparable to the imported product.
- r. The industry is suffering from gross underutilization of production capacities. To compound the difficulties of the domestic producers, the sudden surge in imports is further impacting the capacity utilization of the domestic producers in India.
- s. The Applicant has submitted that that since the product cannot be kept in stock for long, the production has been considered as sales.
- t. Apr.-Dec.2018 share of Malaysia in imports were 12% and other countries share was 88%. However, post December the share of imports of Malaysia surged to 78% whereas the market share of other countries slipped to 22%.
- u. Quarterly analysis shows that share of imports in relation to production had declined to 2% in the Q3 of 2018-19 which increased to 75% in Q1 of 2019-20. Similarly, share of imports in relation to consumption had declined to 1% in the Q3 of 2018-19 which increased to 40% in Q1 of 2019-20. Thus, imports in absolute as well as relative terms have increased significantly in the POI.

- v. The entire surge in imports have happened after the customs duty change in Jan., 2019. Therefore, the injury to the domestic industry is required to be examined considering Jan.-June, 2019 period in comparison to the immediate preceding year (i.e., pre-surge period).
- w. The decline in production/sales becomes evident on comparison of the period April-Dec 2018 with that of POI (Jan-June 2019). The Indian production/sales was *** MT in April-Dec 2018 which declined to *** MT in the POI, i.e., a decline of more than 2.4%. The domestic industry has not been able to sell the subject goods due to presence of imports in the market which have taken over the domestic market.
- x. The capacity utilization of domestic producers has declined significantly with the surge in imports. Whereas the capacity utilization was 43% before surge started, it declined to 39% and thereafter 31% in just two quarters of surge.
- y. Domestic producers have significant underutilized capacities. The industry has not been able to utilize its capacity despite increase in demand because of increase in imports from Malaysia
- z. Market share of domestic producers had increased to 69% in pre-surge period, the same declined to 65% and thereafter 54% in just two quarters of surge in imports.
- aa. Profit of the domestic producers from production and sale of RBD Palmolein have declined drastically with the surge in imports. The domestic producers cannot afford to match the import price of RBD Palmolein after processing imported crude oil, because that will make it difficult for them to even recover their cost. Thus, many of the domestic producers have started importing RBD Palmolein in order to remain present in the market. Resultantly, the domestic producers have lost significant profits from production and sale of RBD Palmolein.
- bb. The imports are suppressing the domestic prices, resultantly, the domestic industry is not able to take up the production activity.
- cc. In addition to the serious injury already inflicted on the industry, increased imports of product were threatening serious injury to the industry because (a) The volume of imports has increased significantly in a relatively short period of time (b) The price difference between the domestic and imported product has led to increase in imports of subject goods from Malaysia. (c) The producers from Malaysia are holding significant unutilized capacities resultantly producers and exporters from Malaysia are continuously looking for additional markets to the extent possible. (d) The producers in Malaysia are one of the largest producers and exporters of subject goods in the world, second only to Indonesia.
- dd. Existence of significant Government support to Malaysian producers would continue to keep them viable in a situation of insufficient duty differential. The Government of Malaysia grants significant support in the form of countervailable subsidies to the grower/processors/producer from the basic stage to the subject goods.
- ee. Various subsidies being provided by the government of Malaysia is leading to lower cost of production of the product for the Malaysian producers vis-à-vis Indian producers. Resultantly, as soon as the customs duty differential declined from previous 10% to 5%, imports surged from Malaysia.
- ff. Applicant requests safeguard measure for the period for which there shall be duty differential of less than 10%. While 10% duty differential itself is inadequate, the same is bare minimum for the industry to prevent the present injury being suffered by the domestic industry
- gg. Article 5 of the CECA deals with provisions pertaining to “Notifications and Consultations Article 5.6 (1) says that the obligation on a party initiating bilateral safeguard investigation is to notify the other party immediately upon initiation of such investigation which has been done in the present case.
- hh. Article 5.6 (6) deals with definitive measures and Article 5.5(5) specifically deals with provisional measures. It may be seen that consultations shall be initiated immediately upon request from the other party i.e., Malaysia in the present case. Thus, after notification of

provisional measures, GOM could seek such consultation. However, there is no provision which requires GOI to hold consultation prior to invoking interim measures. To this extent, arguments of GOM are without sufficient legal basis.

- ii. Para 6.2 of the written submissions submitted by the Government of Malaysia, has been claimed confidential in entirety. Such claims of excessive confidentiality have prevented the Applicant from providing any comment whatsoever. The Applicant is unable to give rejoinder of the submissions filed by the other party for that particular argument which was claimed confidential. In no way the parties should be allowed to claim the entire argument as confidential and there should be proper reasoning for claiming any information as confidential.
- jj. There is no demand supply gap. The Indian capacities for the product are in the region of 1.30 crores MT, reasonably higher than the demand for the product in the Country. The Indian industry has capacities sufficient to meet the present and potential demand for the product in the country.
- kk. Para 29 of the preliminary findings show that the Indian domestic production was *** in 2017-18 and constituted around 66% of the Indian consumption. Thus with increase in demand there is no reason for decline in Indian production to ***MT, i.e., by 9% particularly when the Indian industry is having surplus capacity.
- ll. Indian capacity has always been higher than consumption in the country. This has also been noted by Government of Malaysia in their submission. Thus, to attribute incompetency of domestic producers to produce as a reason for imports is baseless and inappropriate when made at the level of a Government. The significant increase in imports at low price has forced the domestic industry to reduce their production.
- mm. The fact of imports made by the domestic producers was admitted by the Applicant at the stage of application itself. The imports are happening only because imported subject goods are available at a price materially below cost of CPO processed into RBD Palmolein. The fact that the imports are occurring at low prices and the domestic industry cannot import CPO, process the same and sell the subject goods at matching prices gets established by the imports of RBD Palmolein by the producers themselves. No producer would invest in refining capacities and thereafter keep the same idle, and resort to imports. It is a pity that refineries with massive investment and employment are getting converted into small time traders.
- nn. The injury to the domestic industry is highlighted from the fact that the Domestic industry's production has shown an increase by 16.22% from *** MT in 2016 to *** MT in 2019. The same however declined thereafter in a short span of time to *** MT in the POI despite increase in demand. Further, since the duty levels changes w.e.f. 1st Jan., 2019, the DG should consider the situation just before that and compare with the situation just thereafter.
- oo. The Indian industry was already facing significantly underutilized capacities and with surge in imports, capacity utilization of the industry has declined very significantly. The Indian industry is not utilizing even half of its capacities. Paragraph 42 of the Provisional findings itself shows that the capacity utilization declined to mere 31% in Q1 of 2019-20 which was 43% in Q3 of 2018-19 (pre surge period). Since the duty levels changes w.e.f. 1st Jan., 2019, the DG should consider the situation just before that and compare with the situation just thereafter.
- pp. It is admitted that the industry had been suffering on account of other factors as well. However, significant increase in imports have led to further decline in capacity utilisation of the domestic industry and have impacted the viability of the domestic industry. The cause of claimed injury during January 2019 to June 2019 is due to surge in Malaysian imports, whereas the cause of injury in earlier periods were due to reasons other than surge in imports from Malaysia. The DG should see causal link during the surge period and with duty differential issue leading to surge.

- qq. The share of imports from Indonesia was higher between the years 2016 to 2018. However, it changed during the period January 2019 to June 2019. The GOM itself has highlighted the problem. When Indonesian producers were leading the imports, why Malaysian imports increased so significantly. The answer to this query is in the customs duty differentials and the same are required to be addressed by bridging the gap.
- rr. The industry requests a protection to the fullest extent of measures permissible under the agreement for period for which the duty differential shall be less than 10%.
- ss. Decline in production and capacity utilization is evident even from the decline in imports of crude palm oil. The imports of CPO declined sharply during this period.
- tt. The Indian industry is operating their plant below 1/3rd of their capacities. Whereas the consumption of RBD Palmolein in the country is in the region of 80 lacs MT, the country has capacities in the region of 130 lac MT. Imports of RBD Palmolein are thus totally unnecessary.
- uu. Number of man-hours deployed in processing of product under consideration has declined in the current period. Considering annual loss of production to the extent of *** lacs, the employment deployed for the product has declined by about ***.
- vv. The productivity of the Indian industry has declined significantly in the POI. There are no other factors that may be attributing to the serious injury to the domestic industry other than increased imports.
- ww. The landed price of imports is significantly lower than the selling prices of the domestic industry. The domestic industry is losing sales opportunities as well as normal margin. Consequently, sales, profits, return on investment and cash flow is declining due to continued presence of low price imports.
- xx. Increased imports have led to increase in market share of imports and reduction in market share of the domestic industry. The Applicant has requested safeguard measure as provided under the Rules. The price difference between the target price, considering the import price of crude, processing costs involved and reasonable profit (5%) and landed price of imports is about 18%.
- yy. The purpose of seeking safeguard measure is to enable the domestic industry to improve its capacity utilization so that the domestic industry is able to survive. The Applicant has requested safeguard measures for one year. Applicant has also requested for imposition of provisional safeguard measure. It was submitted that the interim measures are imperative in view of the steep deterioration in performance of the domestic industry as a result of increased imports of the product under consideration.
- zz. It was also submitted that the imports from Malaysia have increased significantly whereas the production, sales and resultantly the capacity utilization of Indian industry has declined significantly.
- aaa. While the GOI may consider a dumping, subsidy or general safeguard action to address the injury being suffered by the domestic industry for quite some time, whatever action is taken, the present duty differential between CPO & RBD Palmolein and between Malaysia & Indonesia needs to be addressed as an independent issue. Invoking other actions will not address this issue without changing the customs duty levels. Thus, while taking other actions, the present safeguard duty in any case needs to be confirmed.
- bbb. Separately, basic customs duty under ASEAN agreement and present agreement have also changed w.e.f. 1st Jan., 2020. While the differential between crude and refined is insufficient for sustainable operations of the domestic producers, in any case, the customs duty under the two agreements is now the same. Therefore, safeguard duty in the present agreement without similar duty under ASEAN agreement would mean a futile safeguard duty, as the consumers would utilise benefit under ASEAN agreement.
- ccc. However since imports of the subject goods are now under restricted list, it appears that the product shall now remain regulated. In view of this recent development, it appears that it

may not be necessary to impose safeguard duty beyond the current period of 6 months. However, should the situation in future change due to any development unforeseen at this stage, in any case, industry shall appropriately approach the Government for appropriate remedy.

Views of the Government of Malaysia (GOM)

12. Submissions made by Government of Malaysia are as follows:

- a. DGTR has failed to adhere to commitments in the CECA, since the GOM was not given adequate opportunity for prior consultations before the safeguard measure was initiated on 14 August 2019 as per Article 5.6(5)
- b. As per para 29 of the Preliminary Findings on imports in relation to production and consumption, the Applicant is unable to meet the demand in the Indian market. Imports from Malaysia constituted only around 9.28% of Indian consumption in 2018-19 whereas Indian production was compared to the Indian consumption was 67.52%. Indian production alone was still unable to meet the Indian total consumption in the period 2018-19 and also during POI.
- c. Impact of imports over production and sales is showing decreasing trend. Therefore, the imports did not injure the domestic industry in India. The capacity utilisation has remained in the range of 21% to 43%. Thus this is a problem with the Indian Industry and is not as a result of Malaysian imports.
- d. MITI requested for consultation in accordance with para 6 of MICECA.
- e. Applicant has been unable to meet the local demand of the Product Under Consideration (PUC) in the Indian market. This is evident as during the period of investigation (POI), the domestic production in India only consist *** MT or 59% of India's domestic consumption which is *** MT (Reference to para 29 of Preliminary Findings)
- f. Imports from Malaysia during period of 2018-2019 only constituted 53.55% of the total Indian production and 31.76% of the Indian total consumption. In this regard, the Indian production alone was unable to meet the Indian total consumption over the period of 2016 upto during POI, hence being dependent on sources of imports of the PUC (Reference to para 29 of Preliminary Findings)
- g. Companies named as petitioners in this investigation have been importing the PUC from Malaysia. This ascertains the fact that the domestic industry in India is not able to meet the domestic demand and also not cost efficient. Therefore, they have opted to import the PUC from Malaysia to either further process or trade it domestically.
- h. Domestic industry's production has shown an increase by 16.22% from *** MT in 2016 to *** MT in 2019. The domestic demand has also increased by 4.26% for the same period.
- i. Indian domestic industry failed to fully utilise their production capacity. It was clearly demonstrated in the table in paragraph 42 that the capacity utilisation of the Indian domestic industry only ranged from 31% to 35% between 2016 to POI.
- j. Imports from Malaysia is not the cause of injury suffered by the domestic industry as the inefficient capacity utilisation has been evident since 2016. Imports from Malaysia had accounted for 15% of the domestic industry's production in that year, and 54% of the domestic industry's production in the POI.
- k. Domestic industry has a huge capacity to produce up to *** MT annually. There has always been a huge gap between the demand and supply, whereby during the POI, the domestic demand was *** MT but the supply by the domestic producers was only *** MT. The gap in the demand and supply has been compensated with imports by companies who amongst others have been named as the petitioners in this investigation due to the cost advantage of imported product under consideration
- l. Indian domestic industry's performance in terms of production, capacity utilisation, sales have been mediocre since 2016.

- m. Share of imports from Indonesia have also been consistently higher than the share of imports from Malaysia between 2016 up to 2018
- n. If objective of the safeguards measure is to protect the domestic producers / refiners in India against imports of the PUC from Malaysia, the DGTR is urged to stop imports of the PUC from all sources, such as Indonesia or other countries producing/exporting the PUC by imposing a global safeguard measure. By way of the imposition of this bilateral safeguard measure, imports of the PUC from other sources, namely Indonesia or other countries producing/exporting the PUC will be seen to rise, thus defeating the objective to protect the domestic industry.

Views of RSH Agro Products limited, Guwahati and Budge Budge refineries Ltd

13. Submissions made by RSH Agro Products limited, Guwahati and Budge Budge refineries Ltd are as follows:
- a. Government used to have a duty differential of 15% between RPO and CPO , but the duty difference has come down to 10% after recent duty hike from Malaysia, which makes it difficult for the refiners to survive.
 - b. The existing differential tariff value is low which is also an unfavourable circumstance for the domestic edible oil refiners, it is suggested that at least \$40-50 difference should be maintained.
 - c. Imports of Refined palm oil from neighbouring countries like Bangladesh, Nepal, Srilanka etc is under 0% subject to value addition norms. Palm oil is grown mainly in Malaysia and Indonesia, however due to SAFTA they are trying to evade duties.
 - d. To safeguard the interest of the domestic industry it is requested that (a) reinstatement of custom duty differential between RPO and CPO to be 15% atleast (b) Maximise differential tariff value between RPO and CPO by \$40-\$50 (to restrict edible oil imports under SAFTA and SAARC countries) (c) to restrict edible oil imports from SAARC countries under SAFTA without NOC from DRI (d) refineries in north east may be granted a 15% special rebate/refund of custom duty amount as they are situated at land locked/remote area so that they stay viable and competitive.
 - e. In spite of substantial capital investments in their refineries factory sheds, plant and machineries, the average health of domestic edible oil industries is adversely affected. These industries are also labour intensive. Non-functioning of the domestic edible sectors will result in acute crisis in mitigating consumer demand clubbing with additional unemployment risk of people engaged in this trade.

C. Examination by the Director General

14. The information made available by the interested parties in their submissions, have been considered by the Director General for the purpose of the present determination and the Director General notes the following:

C.1 Product under Consideration (PUC)

15. The product under consideration in the present investigation is “Refined Bleached Deodorised Palm Oil” and “Refined Bleached Deodorised Palmolein” (also known as RBD Palm Oil and RBD palmolein, respectively), falling under the HS code 15119010 and 15119020 of the Customs Tariff Act. RBD Palmolein is refined, bleached and deodorized form of palm oil which is extracted after crushing palm fruit. Product under consideration is commonly used to formulate trans-free fats such as margarine, shortening and vegetable ghee.

C.2 Domestic Industry

16. Rule 2 (b) of the Rules, provides as follows:

“domestic industry” means, with respect to an imported good, the producers -

- (i) *as a whole of the like good or directly competitive good in India; or*

- (ii) *whose collective production of the like good in India constitutes a major proportion of the total domestic production of the such good in India.*

17. Further, Rule 4 provides as follows with regard to filing of application:

The Director General shall, on receipt of a written application by or on behalf of the domestic producer of like good or directly competitive good, initiate an investigation to determine the existence of serious injury or threat of serious injury to the domestic industry, caused by increased imports of an originating good as result of the reduction or elimination of a customs duty under the Trade Agreement

18. The application has been filed by the Solvent Extractors' Association of India on behalf the domestic producers of "Refined Bleached Deodorised Palm Oil" and "Refined Bleached Deodorised Palmolein" in India. The application contains information for the Indian industry as a whole. The following domestic producers have specifically sought imposition of bilateral safeguard measures.

- a. 3F Industries Ltd.,
- b. Adani Wilmar Ltd.,
- c. COFCO International,
- d. Emami Agrotech Ltd,
- e. Gemini Edible Fats & Oils Ltd.
- f. Gokul Agro Resources Ltd,
- g. Liberty Oil Mills Ltd.,
- h. Ozone Procon Pvt. Ltd.,
- i. Ruchi Soya Industries Ltd. (6 Units),

19. It is considered that the application has been filed on behalf of the "domestic producers as a whole" of the like article in India, and Solvent Extractors' Association of India has been taken as domestic industry for the purpose of this investigation, in terms of Rule 2(b).

C.3 Period of Investigation (POI)

20. The period of January 2019 to June 2019 has been considered as the period of investigation (POI) for the purpose of determination as to whether imports of the subject goods have increased in such quantities so as to constitute "increased imports". The applicable customs duties on Crude Palm Oil and subject goods changed with effect from 1st January, 2019. Neither the domestic laws nor Agreement on Safeguards and Article XIX of GATT nor the Rules, provide any specific guidelines on the period of investigation except the fact that the relevant investigation period should be sufficiently long to allow conclusion to be drawn on increased imports and serious injury or threat of serious injury to the Indian industry. The injury investigation period has been considered as the period 2016-17, 2017-18, April 2018 to December 2018 and the POI. The figures in the present findings for the periods April 2018 to December 2018 and POI have been mentioned on annualised basis in order to be comparable to the previous year period.

C.4 Source of Information

21. Since the subject goods have dedicated customs code, import data for the period from April 2015 to June 2019 have been considered as per import-export data published by Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S). Information with regard to serious injury has been considered for the domestic producers as a whole.

22. Information with regard to serious injury has been provided by the Applicant in respect of domestic producers as a whole. After initiation, the Director General issued questionnaire to the Association directing them to provide information as per prescribed questionnaire from the domestic producers. The said information has been provided by following domestic producers.

- a. Emami Agrotech Ltd
 - b. Liberty Oil Mills Ltd.
 - c. Gemini Edible Fats & Oils Ltd
 - d. Adani Wilmar Ltd.
 - e. Gokul Agro Resources Ltd
 - f. Vimal Oil & Foods Ltd
 - g. Ozone Procon Pvt Ltd
23. The Director General has considered evaluation of injury and serious injury on the following basis:
- a. Parameters such as market share, capacity, production, domestic sales, capacity utilisation, have been determined first for domestic producers as a whole and thereafter also for the participating domestic producers.
 - b. Parameters such as profit, wages, and employment have been examined in respect of all domestic producers on a consolidated basis. These parameters have also been analysed on individual basis with respect to participating domestic producers.
24. For threat of serious injury, the Director General has considered information as made available by the Applicant in their application and additional information submitted after initiation of the investigation. A copy of the information submitted by the Applicant post initiation of investigation has been placed in public file for perusal of the parties to allow them to offer their comments if any, for consideration during final determination of safeguard duty.

C.5 Customs Duty under the CECA

25. Comprehensive Economic Cooperation Agreement between the Government of India and the Government of Malaysia (CECA) and India-ASEAN Free Trade Agreement (AIFTA) provided reduction of customs duty on CPO and RBD Palmolein as mentioned below.

CECA Preferential Tariffs			
	Tariff line	CPO	RPO
	Base Rate	80	90
	Entry into Force (EIF)	72	82
Not Later than	1.1.2012	68	78
	1.1.2013	64	74
	1.1.2014	60	70
	1.1.2015	56	66
	1.1.2016	52	62
	1.1.2017	48	58
	1.1.2018	44	54
	31.12.2018	40	45

	AIFTA Preferential Tariffs		
	Tariff line	CPO	RPO
	Base Rate	80	90
Not Later than	2010	76	86
	2011	72	82
	2012	68	78
	2013	64	74
	2014	60	70
	2015	56	66
	2016	52	62
	2017	48	58
	2018	44	54
	2019	40	50

26. It can be noted that the customs duty differential between CPO and RPO was 10 % during the period from April, 2015 till December, 2018. The customs duty differential however reduced to 5% w.e.f. 01.01.2019. This reduction in customs duty differential has resulted in significant increase in subject imports with consequent decline in imports of crude palm oil.

C.6 Increased Imports

27. Rule 2 (d) of the Rules, provides as follows:

“increased imports” means increase in imports from Malaysia whether in absolute terms or relative to domestic production

28. The Rules require an examination whether imports of the PUC increased in such quantities in absolute and relative terms so as to constitute “increased imports”. The Rules require an analysis of the imports, in both absolute terms and in relation to imports into India, production and consumption in India. Analysis of increased imports of the product under consideration has been conducted having regard to the Rules.

i. Imports from Malaysia in absolute terms:

29. The movement of imports is shown in the table below:

Sl. No.	Period	Volume (MT)		
		Malaysia	Other countries	Total imports
1	2016-17	626,362	2,315,292	29,41,654
2	2017-18	376,136	2,308,482	26,84,618
3	2018-19	696,909	1,729,644	24,26,553
4	Apr.-Dec.2018 (Annualised)	271,099	1,986,498	22,57,597
5	POI (Annualised)	2,596,225	725,210	33,21,435
Imports on quarterly basis (MT)				
1	Q1 18-19	97,239	470,534	5,67,773
2	Q2 18-19	78,879	640,816	7,19,695

3	Q3 18-19	27,206	378,524	4,05,730
4	Q4 18-19	493,584	239,771	7,33,355
5	Q1 19-20	804,528	122,834	9,27,362

30. The imports of the product under consideration have increased significantly in the POI in absolute terms. There is a sudden, sharp and significant increase in imports of PUC during the POI. Imports from Malaysia increased from 626,362 MT in 2016-17 to 2,596,225 MT in Jan-June, 2019 (on annualized basis) thus showing an increase of 314%. Imports from other countries declined from 2,315,292 MT in 2016-17 to 7,25,210 MT in Jan-June, 2019 (on annualized basis).

31. Analysis of quarterly movement in imports shows that imports were 27,206 MT in Oct.-Dec., 2018, which surged to 804,528 MT in Apr-June, 2019 thus showing an a surge of almost 29 times.

ii. Share of increase in imports of subject goods from Malaysia and other countries

32. The share of imports of subject goods from Malaysia and other countries is shown in the table below:

Sl. No.	Period	Share in Imports (%)	
		Malaysia	Other countries
1	2016-17	21%	79%
2	2017-18	14%	86%
3	2018-2019	29%	71%
4	Apr.-Dec.2018	12%	88%
5	POI annualized	78%	22%
Imports on quarterly basis			
1	Q1 18-19	17%	83%
2	Q2 18-19	11%	89%
3	Q3 18-19	7%	93%
4	Q4 18-19	67%	33%
5	Q1 19-20	87%	13%

33. It is noted that imports of the product under consideration from Malaysia in 2016-17 was 21% of total imports into India. There was no material increase in the volume of imports till Dec., 2018 in relation to total imports of the product under consideration in India. However, the imports of subject goods from Malaysia increased significantly to 78% during the POI. Overall share of imports of product under consideration from Malaysia have increased to almost 4 times in the POI as compared to the base year.

iii. Increase in imports in relation to production and consumption in India

34. The movement of imports of subject goods in relation to production and consumption in India is shown in the table below:

Sl. No.	Period	Imports Malaysia	Indian Production	Indian Consumption	Imports in relation to (%)	
		MT	MT	MT	Production	Consumption
1	2016-17	626,362	***	***	***	***

2	2017-18	376,136	***	***	***	***
3	2018-19	696,909	***	***	***	***
4	Apr.-Dec., 2018 (annualized)	271,099	***	***	***	***
5	POI (annualized)	2,596,225	***	***	***	***
6	Q1 18-19	97,239	***	***	***	***
7	Q2 18-19	78,879	***	***	***	***
8	Q3 18-19	27,206	***	***	***	***
9	Q4 18-19	493,584	***	***	***	***
10	Q1 19-20	804,528	***	***	***	***

35. It is noted that imports from Malaysia constituted 15% and 9% respectively of the production and consumption in India in 2016-17. The share of Malaysia, however, surged to 54% and 32% respectively in the Jan-June, 2019. Thus, imports have shown significant increase in imports in relation to production and consumption. The share, in fact, surged to 75% and 40% respectively in the April-June, 2019 period from 2% and 1% respectively in Oct.-Dec., 2018 period. The increase in imports in relation to production and consumption is sharp and significant in such a short period.

C.7 Serious Injury

36. Serious Injury and Threat of serious injury is defined as follows under the Rules:

(c) *serious injury means a significant overall impairment in the position of a domestic industry; and*

(d) *threat of serious injury means serious injury that is clearly imminent and shall be determined on the basis of facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility.*

37. Thus, increase in imports should be such which causes a significant overall impairment in the position of a domestic industry

38. Rule 7 of the Rules further provides as follows:

The Director General shall determine serious injury or threat of serious injury to the domestic industry taking into account, inter alia, the following principles, namely :-

(a) *the Director General shall evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that domestic industry, in particular, the rate and amount of the increase in imports of the originating good in absolute and relative terms, the share of the domestic market taken by increased imports of the originating good, changes in the level of sales, production, productivity, capacity utilisation, profits and losses and employment;*

39. It is noted that evaluation of the listed parameters needs to take into account peculiarities of different industries and situations. The Director General has therefore examined serious injury to the domestic industry, having regard to the facts of the present case and the situation of the industry. Thus, in addition to a technical examination of all the listed factors and any other relevant factors, it is essential that the overall *position* of the industry is evaluated, in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry.

40. Accordingly, in analyzing serious injury and threat of serious injury all factors, which are mentioned in the rules as well as other factors which are relevant for determination of serious injury or threat of serious injury, have been considered. The determination of serious injury or threat of serious injury is based on evaluation of the overall position of the industry, in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry.

41. Rule 3 (b) states as follows:

the Director General shall evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that domestic industry, in particular, the rate and amount of the increase in imports of the originating good in absolute and relative terms, the share of the domestic market taken by increased imports of the originating good, changes in the level of sales, production, productivity, capacity utilisation, profits and losses and employment;

42. The serious injury and threat of serious injury to the domestic industry on account of increased imports of subject goods has been examined by evaluating the following factors as listed under the rules:

i. Increase in imports in absolute and relative terms

43. It is noted that the imports of subject goods have increased significantly in absolute as well as in relative terms in the recent period. Further, the increase in imports is noted under both the situation when it is compared between 2015-16 and January 2019 to June 2019, or with the period immediately preceding the surge period. It is also noted that there was significant increase in imports in April 2019 to June 2019 as compared to preceding quarter.

ii. Production and Sales:

44. The Applicant has submitted that the only source of production is either domestic or imported raw material and the only use of raw material is in production of the product under consideration. They have also claimed that the producers cannot hold either raw material inventories or finished product inventories for long period due to low shelf life of the product at every stage from the stage of plucking of flower to consumption of oil. It was also the contention of the Applicant that the consumption norms for production of product from the raw material are not only fairly standardized but they can also be considered globally the same. The Applicant has also submitted relevant material from the Round Table on Sustainable Palm Oil evidencing therein the input output ratio between CPO and RBD Palmolein. The Applicant has also submitted that sales can be considered at the same level of production as the product under consideration cannot be kept in stocks for long time.

45. In view of the above, gross Indian production and domestic sales have been assessed considering such consumption norms. For the purpose, consumption of raw material i.e. CPO has been considered on the basis of imports of CPO in India, as publicly reported by the DGCI&S.

46. The domestic production and sales following the above stated methodology is as follows:

Sl. No.	Period	Production/Sales	Demand
		MT	MT
1	2016-17	***	7,190,365
2	2017-18	***	7,995,216
3	2018-19	***	7,510,304
4	Apr-Dec'18 annualized.	***	7,237,288
5	POI annualized	***	8,174,382

47. It is noted that the demand increased during the POI whereas, the Indian production and sales increased upto April-Dec 2018 period and have declined thereafter in the POI. The Indian production/sales was *** MT in April 2018 to December 2018 which declined to *** MT in the POI i.e. a decline of more than 2.4%.

iii. Capacity utilization

48. The details of capacity and capacity utilisation are as follows:

Period	Capacity	Capacity
	MT	%
2016-17	13,900,000	***
2017-18	13,900,000	***
2018-19	13,900,000	***
Apr-Dec'18	13,900,000	***
POI	13,900,000	***

Period	Capacity (MT)	Capacity	Production
2016- 17	1,39,00,000	***	***
2017-18	1,39,00,000	***	***
2018-19	1,39,00,000	***	***
2019-20 (Q1)	1,39,00,000	***	***
Q1 17-18	34,75,000	***	***
Q2 17-18	34,75,000	***	***
Q3 17-18	34,75,000	***	***
Q4 17-18	34,75,000	***	***
Q1 18-19	34,75,000	***	***
Q2 18-19	34,75,000	***	***
Q3 18-19	34,75,000	***	***
Q4 18-19	34,75,000	***	***
Q1 19-20	34,75,000	***	***
Apr-Dec'18	1,04,25,000	***	***
POI Jan-June'19	69,50,000	***	***

49. It is noted that domestic industry has significant underutilised capacity and their capacity utilisation has gone down during the POI.

iv. Market share of the domestic industry

50. The movement of market share is as follows:

S. No.	Period	Market Share (%)	
		Malaysia	Indian industry
1	2016-17	9%	59%
2	2017-18	5%	66%
3	2018-19	9%	68%
4	Apr-Dec'18	4%	69%
5	POI	32%	59%
6	Jan.-March, 2019	24%	65%
7	Apr-June, 2019	40%	54%

51. It is noted that market share of domestic industry has declined whereas market share of imports of subject goods from Malaysia have increased during the POI as compared to earlier years.

v. Employment and Productivity

52. The Applicant has claimed that manhours deployed in processing of product under consideration has declined significantly in the current period and considering annual loss of production/sales to the extent of *** lacs (considering sales in Oct-Dec 2018 and POI), the employment deployed for the product has declined by about ***. Given the fact that there is a decline in production of subject goods, the productivity has declined.

vi. Profit/loss

53. Cost of subject goods and its fair price after conversion from imported crude refined oil is as follows:

	Unit	POI Annualised
Crude Import Volume	MT	***
Import value Rs. Lakhs	Rs.Lakhs	***
CIF Rate Rs./MT	Rs./MT	***
Customs duty %	%	***
Customs duty amount	Rs./MT	***
Cess amount	Rs./MT	***
Landed cost	Rs./MT	***
Consumption factor		***
RM cost	Rs./MT	***
Less: By product	Rs./MT	***
Conversion Cost	Rs./MT	***
Net value of Palm Oil	Rs./MT	***
Profit	5%	***
Fair price	Rs./MT	***

54. As against the above fair price, the landed price of imported RBD Palmolein from Malaysia is as follows in the POI:

Particulars	UOM	Amount
Volume (MT)	MT	2,596,225
CIF rate	Rs./MT	40,997
Customs duty	%	45%
Customs duty amount	Rs./MT	18,449
Cess amount	Rs./MT	553
Landed price of RBD Palmolein	Rs./MT	60,000

55. It is noted that the domestic producers themselves started importing RBD Palmolein in order to remain in the market. Resultantly, the domestic producers have lost significant production and resultant sales. This has resulted in significant loss of profits to the domestic producers. Considering the reasonable profit of Rs 1,500 per MT, the estimated profitability of the domestic industry declined significantly over the period, as is noted from the following:

	Sales	Profits
	MT	Rs. Crs
2016- 17	42,47,839	***
2017-18	53,08,775	***
Q1 18-19	9,52,452	***
Q2 18-19	12,69,789	***
Q3 18-19	15,01,645	***
Q4 18-19	13,46,697	***
Q1 19-20	10,77,169	***

56. It is noted that estimated profits of the domestic industry declined significantly during the POI.

vii. Price suppression/depression and Price undercutting:

57. Comparison of landed price of subject goods with that of the reasonable price derived for the subject goods is shown in the table below:

Particulars	Unit	Amount
Reasonable price of RBD Palmoelin	Rs./MT	***
Landed price of RBD Palmolein	Rs./MT	***
Difference	Rs./MT	***

58. It is noted that landed price of RBD Palmolein is significantly below the level of reasonable price of RBD Palmolein required by the domestic producers, should they import CPO and process the same into RBD Palmolein. This shows that the imports are suppressing the prices of the domestic producers to such an extent that the domestic producers are not even undertaking production activities to that extent. The difference between landed price of imports and reasonable price is significant, indicating significant price undercutting by the imports of subject goods from Malaysia.

C.8 Injury analysis of Domestic producers who have provided data

59. In addition to the analysis of performance of the industry in respect of domestic producers as a whole, the Director General has analysed performance of those companies who provided information post initiation. Following domestic producers have provided information pertaining to capacity, production, sales, employment, wages, productivity and profits.

- a. Emami Agrotech Ltd
- b. Liberty Oil Mills Ltd.
- c. Gemini Edible Fats & Oils Ltd
- d. Adani Wilmar Ltd.
- e. Gokul Agro Resources Ltd
- f. Vimal Oil & Foods Ltd
- g. Ozone Procon Pvt Ltd

60. It is noted that production and sales of these companies were increasing till Dec., 2018. The production and sales however declined by 23% (POI) and 31% (April-June, 2019). The decline in production and sales is considered significant. Consequently, the capacity utilisation and profits of these companies have also declined significantly. Employment and wages have largely remained the same. Productivity, however, declined significantly.

61. The performance of individual companies was also examined over the same period. It is noted that production, productivity and sales of most of these companies were increasing till Dec., 2018 and declined significantly during the POI

Year	Production (Quarterly) (in MT)						
	Gemini	Ozone	Gokul	Emami	Adani	Liberty	Vimal
2016- 17	***	***	***	***	***	***	***
2017-18	***	***	***	***	***	***	***
Q1 18-19	***	***	***	***	***	***	***
Q2 18-19	***	***	***	***	***	***	***
Q3 18-19	***	***	***	***	***	***	***
Q4 18-19	***	***	***	***	***	***	***
Q1 19-20	***	***	***	***	***	***	***

Year	Capacity Utilisation (in %)						
	Gemini	Ozone	Gokul	Emami	Adani	Liberty	Vimal
2016- 17	***	***	***	***	***	***	***
2017-18	***	***	***	***	***	***	***
Q1 18-19	***	***	***	***	***	***	***
Q2 18-19	***	***	***	***	***	***	***
Q3 18-19	***	***	***	***	***	***	***
Q4 18-19	***	***	***	***	***	***	***
Q1 19-20	***	***	***	***	***	***	***

Year	Productivity Per Day (in MT)						
	Gemini	Ozone	Gokul	Emami	Adani	Liberty	Vimal
2016- 17	***	***	***	***	***	***	***
2017-18	***	***	***	***	***	***	***
Q1 18-19	***	***	***	***	***	***	***
Q2 18-19	***	***	***	***	***	***	***
Q3 18-19	***	***	***	***	***	***	***
Q4 18-19	***	***	***	***	***	***	***
Q1 19-20	***	***	***	***	***	***	***

Year	Production (Indexed)						
	Gemini	Ozone	Gokul	Emami	Adani	Liberty	Vimal
2016- 17	100	100	100	100	100	100	100
2017-18	193	1,747	145	124	111	173	40

Q1 18-19	351	1,949	58	86	94	50	-
Q2 18-19	301	2,159	86	117	105	46	-
Q3 18-19	415	2,869	201	149	150	145	-
Q4 18-19	368	2,360	91	131	124	202	-
Q1 19-20	330	762	66	116	87	212	-

Year	Capacity Utilisation (Indexed)						
	Gemini	Ozone	Gokul	Emami	Adani	Liberty	Vimal
2016- 17	100	100	100	100	100	100	100
2017-18	193	1,747	145	124	111	173	40
Q1 18-19	351	1,949	58	86	94	50	-
Q2 18-19	301	2,159	86	117	105	46	-
Q3 18-19	415	2,869	201	149	150	145	-
Q4 18-19	368	2,360	91	131	124	202	-
Q1 19-20	330	762	66	116	87	212	-

Year	Productivity Per Day (Indexed)						
	Gemini	Ozone	Gokul	Emami	Adani	Liberty	Vimal
2016- 17	100	100	100	100	100	100	100
2017-18	193	1,747	145	124	111	173	40
Q1 18-19	351	1,949	58	86	94	50	-
Q2 18-19	301	2,159	86	117	105	46	-
Q3 18-19	415	2,869	201	149	150	145	-
Q4 18-19	368	2,360	91	131	124	202	-
Q1 19-20	330	762	66	116	87	212	-

C.9 Conclusion on Injury

62. It is, thus, concluded that the imports of the product under consideration have increased significantly in absolute terms and in relation to gross imports into India, Indian production and consumption. As a result of significant surge in imports from Malaysia, the domestic producers have suffered serious injury in terms of significant decline in production, sales, capacity utilization, market share, profits out of refining operations, and manpower deployed for processing the product. Considering the performance of the domestic producers in respect of various parameters, it is concluded that the domestic industry has suffered serious injury as a result of increased imports of the product under consideration from Malaysia.

C.10 Causal Link

63. A comprehensive evaluation of parameters enumerated above demonstrates that serious injury had been caused by increased imports of subject goods from subject country during the POI. For the purpose of determining causation, all relevant factors of an objective and quantifiable nature

having a bearing on the situation of the industry have been evaluated. In the instant case, the following are relevant in this regard:

- a. The imports of PUC had increased significantly in the POI in absolute as well as relative terms.
 - b. The market share of domestic producers had declined whereas that of imports from Malaysia had increased.
 - c. The landed price of import was significantly lower than the reasonable price of subject goods in the POI.
 - d. Domestic producers were forced to import goods in order to maintain their market presence.
 - e. Sales, production, capacity utilisation, manpower deployed and profits of the domestic producers declined as a result of increased imports in the POI.
64. It is, thus, evident that injury to the domestic industry had been caused by the increased imports during the POI and there was a causal link between increased imports of subject goods from Malaysia and serious injury to the domestic industry.

C.11 Threat of Serious Injury

65. The Rules provides as follows:

“threat of serious injury” means serious injury that is clearly imminent and shall be determined on the basis of facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility;

66. It is noted that imports of subject goods from Malaysia were entering the Indian market in significant increased quantities in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India. The domestic industry’s capacity was underutilized and the intensified imports from Malaysia had adversely impacted the situation. The difference between the landed price of imports of subject goods and the reasonable price of subject goods along with the fact of huge capacities with export oriented producers in Malaysia indicated, at the time of issuance of preliminary findings, that the subject goods from Malaysia are likely to remain lucrative, posing further threat of injury to the domestic industry. However, since the imports of subject goods have been put under the “restricted category” vide Notification No. 39/2015-2020 dated 8th January, 2020 and also the fact that the duty differential between Crude Palm Oil and subject goods have become 7.5% under both CECA and ASEAN Agreement, it is noted that the imports from Malaysia under CECA appear to pose no further threat to the domestic industry.

D. Conclusion

67. It is noted that after examining the critical circumstances pertaining to the present case, the Director General had provisionally concluded that the injury being suffered by the domestic industry was on account of intensified increased imports of the subject goods from Malaysia and had recommended provisional duty for a period of 180 days vide Notification No. 22/4/2019 dated 26th August 2019. The Central Government imposed the provisional duty vide Notification No. 29/2019-Customs dated 4th September, 2019 and the said duty is in force till 2nd March 2020.
68. Meanwhile, when the investigation was underway, the Government amended the import policy of items under HS Code 151190 10 (Refined Bleached Deodorised palm oil, HS Code 151190 20 (Refined Bleached Deodorised Palmolein) and HS Code 151190 90 (others) vide Notification No 39/2015-2020 dated 8th January 2010 thus placing the subject goods under “Restricted” category. It has also been brought to the notice by the domestic industry that basic customs duty under ASEAN agreement (which includes Malaysia) and CECA has also changed w.e.f. 1st Jan., 2020. Now, the difference between crude palm oil and Refined Palmolein/Palm Oil is 7.5% in both these Agreements. It has also been submitted that while the differential between crude and refined is insufficient for sustainable operations of the domestic producers, in any case, the customs duty under the two agreements is now the same. Therefore, safeguard duty in the present agreement without similar duty under ASEAN agreement would mean a futile safeguard duty, as the consumers would utilise benefit under ASEAN agreement. It has also been submitted that since imports of the subject goods are now under restricted list, the product shall now remain regulated.

In view of these recent developments, it appears that it may not be necessary to impose safeguard duty beyond the current period of 180 days.

69. In view of the above stated facts, it is considered that the bilateral safeguard duty imposed vide notification no 29/2019-customs dated 4th September, 2019 under the CECA on the import of Refined Bleached Deodorised Palm Oil” and “Refined Bleached Deodorised Palmolein” for a period of 180 days from the date of imposition of the provisional duty is sufficient in the present circumstances.

E. Recommendations

70. The Preliminary Findings issued vide Notification No. 22/4/2019 dated 26th August, 2019 is therefore confirmed. The Director General recommends imposition of bilateral safeguard duty on imports of subject goods from the subject country in the form and manner described in the Preliminary findings issued vide Notification No. 22/4/2019 dated 26th August, 2019 under the CECA on the import of Refined Bleached Deodorised Palm Oil” and “Refined Bleached Deodorised Palmolein” for a period of 180 days from the date of imposition of the provisional duty by the Central Government issued vide Notification No. 29/2019-Customs dated 04th September, 2019.
71. The Director General, in view of the reasons recorded earlier, does not recommend further extension of bilateral safeguard duty.

BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. and Director General